www.tamsasanket.com
वर्ष: 06 || अंक 33 || लखनऊ
रविवार
03 मई 2026 || पृष्ठ: 04 || मूल्य: ₹ 2
आज़ादी का अमृत महोत्सव
समूह संपादक- डॉ. ओ.पी. मिश्रा
https://epaper.tamsasanket.com

दैनिक तमसा संकेत

लखनऊ व अम्बेडकर नगर से एक साथ प्रकाशित
» डॉ. लोहिया की जन्म भूमि से सर्वप्रथम प्रकाशित समाचार पत्र

मौसम
सूर्योदय: 05:27
सूर्यास्त: 06:40
अधिकतम: 34°00
न्यूनतम: 24°00

» पेज 03

विशेष समाचार | सार्वजनिक बहस का मुद्दा... » पेज 02 | लखनऊ डीएम के सामने... » पेज 04 | बिग बॉस 17 के विजेता मुनव्वर ...

15 बूथों पर दोबारा वोटिंग में भी बंपर मतदान

साउथ 24 परगना में बीजेपी-टीएमसी कार्यकर्ताओं के बीच झड़प, फालता में टीएमसी कार्यकर्ताओं पर मारपीट का आरोप

री-पोलिंग

तमसा संकेत, एजेंसी

कोलकाता। पश्चिम बंगाल में डायमंड हार्बर और मगराहाट पश्चिम विधानसभा के कुल 15 बूथों पर शनिवार को दोबारा मतदान हुआ है। साउथ 24 परगना में TMC और भाजपा कार्यकर्ताओं के बीच झड़प हुई। इस दौरान सुरक्षाबलों ने दोनों पक्षों को शांत कराया। वहीं फालता में वोटर्स ने TMC कार्यकर्ताओं पर हमले का आरोप लगाया। उन्होंने बताया कि वोटिंग के बाद TMC के लोगों ने उनके साथ मारपीट की। जब वे इसका विरोध कर रहे थे तो पुलिस ने उन पर लाठीचार्ज किया। कई लोगों को पैर में, सिर में और हाथ में चोट आई है। वहीं, TMC ने आरोप लगाया कि मगराहाट के बूथ नंबर 127 पर सुरक्षाबलों ने हमारे कैंप में तोड़फोड़ की और कार्यकर्ताओं से मारपीट की। शाम 5 बजे तक मगराहाट पश्चिम के 11 बूथों में 86.11% और डायमंड हार्बर के 4 बूथों में 87.60% वोटिंग हुई। वहीं चुनाव आयोग ने बंगाल में 165 अतिरिक्त काउंटिंग ऑब्जर्वर और 77 पुलिस ऑब्जर्वर तैनात किए हैं। दक्षिण 24 परगना की 2 विधानसभा सीटों पर हो रही दोबारा वोटिंग से जुड़े अपडेट्स के लिए नीचे ब्लॉग से गुजर जाइए ममता ने एग्जिट पोल के अनुमानों को सिरे से खारिज करते हुए इसे "स्टॉक मार्केट में हेरफेर करने की कोशिश" बताया। उन्होंने कहा कि पहले भी 2021 और 2024 में ऐसे प्रयास हुए थे और इस बार भी वही दोहराया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स (CAPF) पर TMC कार्यकर्ताओं के साथ दुर्व्यवहार का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि जिन लोगों ने कथित तौर पर इस तरह की कार्रवाई का सामना किया है, पार्टी उन्हें सम्मानित करेगी। भाजपा के सभी विधानसभा के उम्मीदवार अपने-अपने चुनाव क्षेत्रों में मंदिरों में जाकर पूजा-अर्चना करेंगे।

» (शेष पेज 04 पर)

पश्चिम बंगाल के 15 बूथों पर दोबारा वोटिंग

अब तक वोटिंग 86.90%

डायमंड हार्बर 87.60%

मगराहाट पश्चिम 86.11%

टीएमसी का दावा- विपक्ष के सीक्रेट डॉक्यूमेंट में सिर्फ 78 सीटें जीतने की उम्मीद

कुणाल घोष ने दावा किया है कि उनके पास विपक्षी पार्टी का एक सीक्रेट डॉक्यूमेंट है, जिसमें 294 सीटों पर उनकी रिव्यू दर्ज है। उन्होंने कहा कि इस डॉक्यूमेंट में विपक्ष ने सिर्फ 78 सीटों पर जीत की संभावना जताई है। जलपाईगुड़ी में 5 सीटों के लिए वोटों की गिनती यूनिवर्सिटी ऑफ नॉर्थ बंगाल के दूसरे कैंपस में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के साथ होगी। अधिकारियों ने शनिवार को तैयारियों का रिव्यू किया। मालबाजार कॉलेज समेत दोनों काउंटिंग सेंटर पर पैरामिलिट्री फोर्स तैनात की गई हैं। पश्चिम बंगाल के साउथ 24 परगना जिले की मगराहाट पश्चिम सीट पर री-पोलिंग के दौरान दिव्यांग महिला ने वोट डाला।

"घोष ने कहा कि कांग्रेस पहले चरण में ही 100 का आंकड़ा पार कर चुकी थी और दूसरे चरण में यह बढ़कर 200 तक पहुंच गई है। उन्होंने भरोसा जताया कि पार्टी चुनाव में मजबूत स्थिति में है। चुनाव आयोग ने वोटों की सुरक्षित, शांतिपूर्ण और पारदर्शी गिनती पक्का करने के लिए पश्चिम बंगाल में 165 अतिरिक्त काउंटिंग ऑब्जर्वर और 77 पुलिस ऑब्जर्वर तैनात किए हैं। कानून-व्यवस्था बनाए रखने और आसानी से गिनती की प्रक्रिया पक्का करने के लिए पहचान वेरिफिकेशन, प्रोटोकॉल लागू किए गए हैं।

- डायमंड हार्बर के फालता में हंगामे के बीच भारी सुरक्षाबल की तैनाती की गई।
- पश्चिम बंगाल के साउथ 24 परगना जिले की मगराहाट पश्चिम सीट पर री-पोलिंग के दौरान दिव्यांग महिला ने वोट डाला।

ईवीएम से छेड़छाड़- झड़प की शिकायत पर दोबारा वोटिंग

दरअसल, 29 अप्रैल को इन बूथों पर दूसरे फेज की वोटिंग के दौरान EVM से छेड़छाड़ और झड़प की शिकायत मिली थी। इसके चलते दोबारा वोटिंग का फैसला लिया गया। ये सभी बूथ दक्षिण 24 परगना जिले में आते हैं।वहीं, TMC ने कोलकाता खुदीराम अनुशीलन केंद्र के रिटर्निंग ऑफिसर के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। पार्टी का दावा है कि पोस्टल बैलेट कवर से छेड़छाड़ हुई है। राज्य की सभी 294 सीटों पर रिकॉर्ड 92.84% वोटिंग हुई। 23 अप्रैल को फर्स्ट फेज की 152 सीटों पर 93.19% मतदान हुआ था। 29 अप्रैल को सेकेंड फेज की 142 सीटों पर 92.48% वोट पड़े। रिजल्ट 4 मई को आएंगे।

ममता बोलीं- टीएमसी 200+ सीटें जीतेगी, एग्जिट पोल स्टॉक मार्केट प्रभावित करने की साजिश

मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने तृणमूल कांग्रेस (TMC) की बड़ी जीत का दावा किया है। शनिवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए काउंटिंग एजेंट्स को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी 200 से ज्यादा सीटों पर जीत हासिल करेगी। पश्चिम बंगाल के साउथ 24 परगना जिले की मगराहाट पश्चिम सीट पर री-पोलिंग के दौरान दिव्यांग महिला ने वोट डाला।

डायमंड हार्बर में एएसपी ने कहा- टीएमसी भाजपा को नेशनल हाईवे ब्लॉक नहीं करने देंगे

डायमंड हार्बर में री-पोलिंग के दौरान TMC और BJP कार्यकर्ताओं के बीच झड़प के बाद एडिशनल SP अभिषेक ने कहा- हम उन्हें नेशनल हाईवे ब्लॉक नहीं करने देंगे। डायमंड हार्बर PD में अभी री-पोलिंग चल रही है और अगर वे नेशनल हाईवे ब्लॉक करते हैं तो यह कोलकाता से कट जाएगा। उनकी मांग पर केस दर्ज किया गया है और इसकी जांच की जाएगी। फालता के हाशिम नगर इलाके में स्थानीय लोग सड़क जाम करके विरोध कर रहे हैं। उनका आरोप है कि TMC के कार्यकर्ता उन्हें परेशान कर रहे हैं। मौके पर CRPF और RAF के जवानों समेत भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। फालता के हासिमनगर की रहने वाली महिला ने आरोप लगया कि TMC कार्यकर्ताओं ने हमारा उत्पीड़न किया। यह सब एक दिन पहले से हो रहा है। टीएमसी के गुंडे हमारे घरों में घुस आए। महिलाओं को परेशान किया और लोगों की पिटाई की।

अमेरिका की हर गलत हरकत का कड़ा जवाब देंगे : ईरान

वो किसी समझौते को नहीं मानता, उसके वादे दिखावटी होते हैं

जानकारी

तमसा संकेत, एजेंसी

तेल अवीव/तेहरान/वॉशिंगटन। ईरान के सीनियर मिलिट्री अधिकारी मोहम्मद जाफर असदी ने आशंका जताई है कि अमेरिका के साथ फिर से युद्ध शुरू हो सकता है। ईरान की फॉर्स न्यूज एजेंसी ने इस बारे में जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि ईरान की सेना पूरी तरह तैयार है और अगर अमेरिका कोई गलत कदम उठाता है, तो जवाब दिया जाएगा। उन्होंने आरोप लगाया कि अमेरिका किसी भी समझौते या वादे का पालन नहीं करता। असदी ने कहा कि अमेरिकी अधिकारियों के बयान और कदम ज्यादातर दिखावटी और मीडिया के लिए होते हैं।

» (शेष पेज 04 पर)

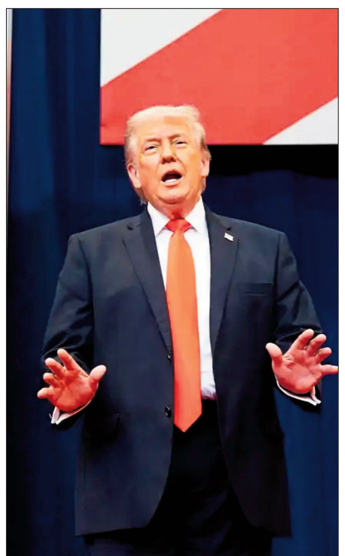

1. **संसदीय मंजूरी की जरूरत नहीं:** ट्रम्प ने ईरान के खिलाफ संभावित सैन्य कार्रवाई को लेकर कहा है कि उन्हें इसके लिए संसद से इजाजत लेने की जरूरत नहीं है। जो लोग इसकी मांग कर रहे हैं, वे देशभक्त नहीं हैं।
2. **ईरान जंग खत्म होने का दावा:** व्हाइट हाउस ने संसद को आधिकारिक तौर पर बताया कि ईरान युद्ध अब खत्म हो चुका है। उस इलाके में अभी भी अमेरिकी सेना मौजूद है, इससे फर्क नहीं पड़ता।
3. **अमेरिका की चेतावनी:** अमेरिका ने कहा कि जो कंपनियां ईरान को होर्मुज से गुजरने के लिए पैसा देती हैं, उन पर अमेरिका पाबंदी लगा सकता है, भले ही वो पैसा चैरिटी के नाम पर ही क्यों न दिया जाए।
4. जहाजों का ट्रैफिक 90% घटा: होर्मुज में जहाजों की आवाजाही लगभग बंद हो गई है। पहले जहां हर दिन करीब 130 जहाज गुजरते थे, अब सिर्फ 10 से भी कम जहाज जा रहे हैं।
5. ट्रम्प को हमले की ब्रीफिंग: अमेरिका की सेंट्रल कमांड (CENTCOM) के कमांडर ने राष्ट्रपति ट्रम्प को ईरान के खिलाफ संभावित हमला करने के विकल्पों की जानकारी दी।

ईरान का नया प्रस्ताव- पहले समुद्री रास्ता खुलेगा, बाद में परमाणु मुद्दे पर बात होगी

ईरान के एक सीनियर अधिकारी ने पुष्टि की है कि उनके नए प्रस्ताव में पहले होर्मुज स्ट्रेट को खोलने और अमेरिकी नाकेबंदी खत्म करने की बात है, जबकि परमाणु मुद्दे पर बातचीत बाद में की जाएगी।

फास्ट न्यूज

देश को जल्द मिलेंगी हाइपरसोनिक मिसाइलें

नई दिल्ली। भारत ने युद्धों की बदलती रणनीति को देखते हुए अत्याधुनिक 'हाइपरसोनिक' मिसाइल तकनीक पर काम तेज कर दिया है। डीआरडीओ प्रमुख समीर वी. कामत ने एक कार्यक्रम में बताया है कि देश जल्द 'हाइपरसोनिक ग्लाइड मिसाइल' और 'हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल' से लैस होगा। इनकी रफ्तार सुपरसोनिक ब्रह्मोस मिसाइल से दोगुनी होगी।

नासिक टीसीएस केस की आरोपी निदा को अग्रिम जमानत नहीं

नासिक। नासिक कोर्ट ने शनिवार को TCS की नासिक यूनिट से जुड़े सेक्सुअल हैरेसमेंट और जबरन धर्म परिवर्तन के मामले में आरोपी निदा खान की एंटीसिपेटरी बेल याचिका खारिज कर दी। प्रॉसिक्यूशन ने कोर्ट में कहा कि आरोप गंभीर हैं और उनसे कस्टडी में पूछताछ जरूरी है। निदा अब तक फरार है। न्यूज एजेंसी PTI के मुताबिक, पब्लिक प्रॉसिक्यूटर अजय मिसर ने बताया कि निदा खान इस केस की मुख्य आरोपियों में से एक हैं। इसी आधार पर कोर्ट ने उनकी अग्रिम जमानत देने से इनकार कर दिया।

धनबाद-कोयला खदान में स्लरी ढहने से 4 मजदूरों की मौत

धनबाद। झारखंड के धनबाद में शनिवार को कोयला स्लरी (कोयले का पाउडर) धंस गई, जिससे 4 मजदूरों की मौत हो गई। ये सभी मजदूर मुनीडीह में BCCL की कोल वाशरी में काम कर रहे थे। इसी दौरान अचानक मलबा गिर गया। आसपास के मजदूरों और स्थानीय लोगों ने तुरंत बचाव काम शुरू किया और प्रशासन को सूचना दी। सूचना मिलते ही प्रशासन मौके पर पहुंचा। मलबा हटाकर चारों मजदूरों के शव बाहर निकाले गए।

4 साल की बच्ची से रेप और हत्या

65 साल का आरोपी गिरफ्तार, सीएम बोले- सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट में होगी

वारदात

तमसा संकेत, एजेंसी

एनसीपी (एसपी) नेता और सांसद सुप्रिया सुले ने आरोपी को कठोर से कठोर सजा देने की मांग की। उन्होंने कहा कि यह घटना बेहद शर्मनाक और मानवता को कलंकित करने वाली है। शिवसेना की राष्ट्रीय प्रवक्ता शाइना ट्ठ ने कहा कि इस दरिंदगी समाज के लिए बड़ा सवाल खड़ा करती है। इस घटना को लेकर लोगों में भारी गुस्सा है।

पुणे। महाराष्ट्र के पुणे में शुक्रवार को एक व्यक्ति ने 4 साल की बच्ची से रेप के बाद पत्थर से कुचलकर उसकी हत्या कर दी। पुलिस ने 65 साल के आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस रिपोर्ट के मुताबिक, बच्ची पुणे के भोर तहसील में रहने वाली अपनी नानी के यहां गर्मी की छुट्टियां बिताने आई थी। भीमराव कांबले (आरोपी) शुक्रवार दोपहर करीब दो बजे बच्ची को बहला-फुसलाकर अपने घर के पास बने तबेले में ले गया। वहां बच्ची से रेप करने के बाद उसकी हत्या कर दी। महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री और एनसीपी (एसपी) नेता अनिल देशमुख ने मामले में आरोपी के लिए फांसी और मामला की सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट में कराने की मांग की थी। इसके बाद महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि सरकार इस मामले की सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट में कराएगी और अपराधी के लिए फांसी की मांग करेगी। काफी देर तक बच्ची घर नहीं लौटी, तो परिजनों ने उसकी तलाश शुरू की। कुछ लोगों ने तबेले में भी बच्ची को तलाशा तो उसका शव बरामद हुआ। पुलिस ने आसपास के सीसीटीवी कैमरों की तलाश की तो एक फुटेज में आरोपी बच्ची को तबेले की ओर ले जाता हुआ नजर आया। पुलिस ने तुरंत भीमराव कांबले को हिरासत में ले लिया। फिलहाल उससे पूछताछ की जा रही है। घटना के बाद गांव के लोगों ने शुक्रवार रात विरोध प्रदर्शन किया और मुंबई-बेंगलुरु हाईवे पर चक्काजाम कर दिया। पुणे ग्रामीण पुलिस अधीक्षक संदीप सिंह गिल ने प्रदर्शनकारियों को आश्वासन दिया है।

ईडी की 2025-26 में सबसे ज्यादा 2,892 रेड

नई दिल्ली। प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने साल 2025-26 में इतिहास में सबसे ज्यादा छापेमारी की। एजेंसी ने कुल 2,892 छापे मारे, जो पिछले साल 1,491 के मुकाबले लगभग दोगुने हैं। ED की सालाना रिपोर्ट 2025-26 के मुताबिक मनी लॉन्ड्रिंग के तहत गिरफ्तारियों में कमी आई। वहीं संपत्ति अटैचमेंट और पीड़ितों को पैसे लौटाने के मामलों में रिकॉर्ड बढ़ोतरी दर्ज की गई। ED ने 712 प्रोविजनल अटैचमेंट ऑर्डर जारी कर 81,422 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त की। यह पिछले साल के 30,036 करोड़ रुपए के मुकाबले 171% ज्यादा है। ये अटैचमेंट PMLA की एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी से पुष्टि के बाद स्थायी होते हैं। ED की गिरफ्तारियों में करीब 27% की कमी आई है। ED ने 156 लोगों को गिरफ्तार किया, जबकि पिछले साल यह संख्या 214 और इससे पहले 272 थी। एजेंसी के मुताबिक अब वह टारगेटेड और सबूत आधारित जांच पर ज्यादा फोकस कर रही है।

पंकज चौधरी ने 5000 महिलाओं के साथ मशाल जुलूस निकाला

आक्रोश

- मशाल जुलूस में महिलाओं ने विपक्ष के खिलाफ जमकर नारेबाजी की।
- मशाल जुलूस में बड़ी संख्या में भापजा पदाधिकारी और कार्यकर्ता शामिल हुए।

तमसा संकेत, एजेंसी

लखनऊ। लोकसभा में महिला आरक्षण बिल पास न होने पर लखनऊ में भाजपा शनिवार को महिला आक्रोश मशाल जुलूस निकाला। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी खुद मशाल जुलूस में पैदल चले। मशाल जुलूस शाम 7 बजे लोकभवन के सामने से शुरू होकर अटल चौक, हजरतगंज पहुंची। इस दौरान सपा-कांग्रेस के खिलाफ जमकर नारेबाजी हुई। मशाल जुलूस में संगठन मंत्री धर्मपाल सिंह, मंत्री रजनी तिवारी, मंत्री विजय लक्ष्मी गौतम, मंत्री प्रतिभा शुक्ला, मेयर सुषमा खर्कवाल, महिला आयोग की सदस्य समेत करीब 5000 कार्यकर्ता शामिल हुए। जुलूस को देखते हुए प्रशासन ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए।

लखनऊ में नहीं आए सीएम और दोनों डिप्टी सीएम

मशाल जुलूस में मंत्रियों ने कहा-

मंत्री प्रतिभा शुक्ला- सपा-कांग्रेस ने हमेशा महिलाओं का अपमान करने का काम किया है।

मंत्री रजनी तिवारी- योगी व मोदी महिलाओं का हक-सम्मान दिलाने का काम कर रहे हैं।

मंत्री विजय लक्ष्मी गौतम- आज महिलाएं घर और समाज में खुद को सुरक्षित महसूस कर रही हैं।

मंत्री कपिल देव अग्रवाल- सपा-कांग्रेस ने महिलाओं के साथ पुरुषों का भी सम्मान छीना है।

परीक्षण : सायरन की आवाज सुनाई दी, सरकार ने इमरजेंसी अलर्ट सिस्टम की टेस्टिंग की

देशभर में करोड़ों मोबाइल पर एकसाथ अलर्ट मैसेज आया

तमसा संकेत, एजेंसी

नई दिल्ली। देशभर में शनिवार सुबह 11:45 बजे कई मोबाइल फोन पर एकसाथ सायरन की आवाज सुनाई देने लगी। स्क्रीन पर हिंदी-अंग्रेजी में एक मैसेज था। सायरन बंद हुआ तो मोबाइल पर मैसेज पढ़कर भी सुनाया गया। इससे कई लोग परेशान हुए, तो कई कन्फ्यूज। यह मैसेज राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, यानी NDMA ने भेजा था। NDMA ने इमरजेंसी में लोगों तक सूचना पहुंचाने के लिए 2 मई को सेल ब्रॉडकास्ट अलर्ट सिस्टम का परीक्षण किया। सरकार ने दो दिन पहले ही मैसेज भेजकर लोगों से अपील की थी कि इमरजेंसी मोबाइल अलर्ट ट्रायल के दौरान यानी टेस्टिंग वाला मैसेज मिलने पर घबराएं नहीं। शनिवार का मैसेज केवल इमरजेंसी के हालात में चेतावनी देने वाले सिस्टम की जांच के लिए भेजा गया था। इमरजेंसी की स्थिति में लोगों को रियल टाइम अलर्ट देने के लिए सरकारी संस्था सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स (C-DOT) ने इंटीग्रेटेड अलर्ट सिस्टम 'SACHET' को विकसित किया है। सचेत नाम का यह सिस्टम कॉमन अलर्टिंग प्रोटोकॉल (CAP) पर आधारित है। इसे देश के सभी 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में एक्टिव कर दिया गया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस सिस्टम के जरिए अलग-अलग प्राकृतिक आपदाओं जैसे मौसम में बदलाव और चक्रवात के अलर्ट दिए जा चुके हैं। अब तक 19 से ज्यादा भारतीय भाषाओं में 134 अरब से ज्यादा SMS अलर्ट भेजे जा चुके हैं। इस सिस्टम का इस्तेमाल हर इमरजेंसी सिचुएशन में लोगों को तुरंत चेतावनी देने के लिए किया जा सकता है।

देशभर में इमरजेंसी मैसेज की एकसाथ टेस्टिंग

शनिवार को देश के सभी राज्यों की राजधानियों और दिल्ली-NCR में सभी मोबाइल फोन पर एकसाथ टेस्टिंग मैसेज भेजा गया। यह मैसेज हिंदी और अंग्रेजी के साथ सभी क्षेत्रीय भाषाओं में भी भेजा गया। मैसेज में बताया गया कि यह केवल परीक्षण है और इस पर कोई एक्शन लेने की जरूरत नहीं है।

सेल ब्रॉडकास्ट तकनीक से रियल-टाइम अलर्ट मिलेगा

NDMA ने मोबाइल SMS को सेल ब्रॉडकास्ट (CB) तकनीक से जोड़ा है। इससे चुने गए इलाके में एक्टिव सभी मोबाइल फोन पर एक साथ अलर्ट मिलेगा। इससे इमरजेंसी के समय रियल टाइम सूचना पहुंच सकेगी।

"रिपोर्ट्स के मुताबिक इस सिस्टम के जरिए अलग-अलग प्राकृतिक आपदाओं जैसे मौसम में बदलाव और चक्रवात के अलर्ट दिए जा चुके हैं। अब तक 19 से ज्यादा भारतीय भाषाओं में 134 अरब से ज्यादा एसएमएस अलर्ट भेजे जा चुके हैं। इस सिस्टम का इस्तेमाल हर इमरजें।

छत्तीसगढ़ में आईईडी ब्लास्ट, 4 जवान शहीद

इसमें डीआरजी के इंस्पेक्टर और कॉन्स्टेबल शामिल

धमाका

तमसा संकेत, एजेंसी

- घायल जवान परमानंद कोर्राम ने भी इलाज के दौरान दम तोड़ दिया।

जगदलपुर। छत्तीसगढ़ के कांकेर-नारायणपुर बॉर्डर पर शनिवार को IED ब्लास्ट में 4 जवान शहीद हो गए। फोर्स शनिवार सुबह कोरोसकोडा के जंगल में सर्च ऑपरेशन पर निकली थी। इसी दौरान नक्सलियों की बिछाई गई IED को डिफ्यूज करते समय अचानक जोरदार धमाका हुआ। मामला छोटेबेठिया थाना क्षेत्र का है। बताया जा रहा है कि धमाका इतना तेज था कि मौके पर मौजूद जवानों को संभलने का मौका तक नहीं मिला। हादसे में घायल जवानों का तुरंत रेस्क्यू किया गया, लेकिन गंभीर चोटों के कारण 3 जवानों ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। घायल जवान परमानंद कोर्राम को बेहतर इलाज के लिए रायपुर एयरलिफ्ट गया था, जहां इलाज के दौरान उसने भी दम तोड़ दिया। कहा कि नक्सलवाद के खत्म होने के राजनीतिक नारे से काम नहीं चलेगा।

सम्पादकीय

जानलेवा लापरवाही, सुरक्षा के न्यूनतम उपाय भी नहीं

जबलपुर में बरगी बांध में एक क्रूज के डूबने से नौ पर्यटकों की मौत को केवल हादसे की संज्ञा देना सच से मुंह मोड़ना होगा, क्योंकि यदि पर्याप्त सतर्कता बरती गई होती तो जनहानि से बचा जा सकता था। यह क्रूज इसलिए डूबा, क्योंकि तेज आंधी से वह असंतुलित हो गया, लेकिन किसी के लिए भी समझना कठिन है कि खराब मौसम की सूचना के बाद भी क्रूज का संचालन क्यों किया गया? इससे भी गंभीर प्रश्न यह है कि क्रूज की सुरक्षा के न्यूनतम उपाय भी क्यों नहीं किए गए? क्रूज में लाइफ जैकेट थीं, लेकिन उन्हें पर्यटकों को पहनने के लिए निर्देशित ही नहीं किया गया। हादसे में किसी तरह बचे और बचाए गए लोगों की मानें तो लाइफ जैकेट तब दी गईं, जब क्रूज डूबने लगा। स्पष्ट है अफरातफरी के माहौल में लोगों को या तो उन्हें पहनने का अवसर नहीं मिला होगा या फिर वे उन्हें सही तरह पहन नहीं सके होंगे। क्रूज डूबने के बाद घटनास्थल पर पहुंचे बचाव दल को लाइफ जैकेट एक बंडल में बंधे मिले। आखिर यह जानलेवा लापरवाही नहीं तो और क्या है? चूंकि बरगी बांध में डूबा क्रूज मध्य प्रदेश पर्यटन बोर्ड की ओर से संचालित किया जा रहा था, इसलिए संबंधित अधिकारियों को जवाबदेह बनाना होगा। केवल घटना पर शोक जताने या फिर मारे गए लोगों के परिवार वालों को मुआवजा देने की घोषणा मात्र से कर्तव्य की इतिश्री नहीं की जानी चाहिए। मध्य प्रदेश सरकार को यह सुनिश्चित करना होगा कि जबलपुर हादसे के लिए जिम्मेदार लोग बचने न पाएं। इसके साथ ही उसे सभी पर्यटन स्थलों में पर्यटकों की सुरक्षा के पर्याप्त उपाय करने चाहिए। इसकी अनदेखी न की जाए कि अतीत में भी राज्य के अन्य पर्यटन स्थलों में हादसे हो चुके हैं और उनमें लोगों की जान गई है। कम से कम तीन हादसे तो पिछले साल ही हो चुके हैं। पर्यटन स्थलों में पर्यटकों की सुरक्षा के मामले में केवल मध्य प्रदेश सरकार को ही नहीं, अन्य राज्य सरकारों को भी चेतना चाहिए, क्योंकि ऐसे स्थलों में सुरक्षा की कमी के चलते रह-रहकर दुर्घटनाएं होती ही रहती हैं। कुछ ही दिनों पहले मथुरा में यमुना में स्टीमर के पलटने से 15 श्रद्धालुओं की मौत हो गई थी। इसी माह के प्रारंभ में हिमाचल के कुल्लू में पर्यटकों से भरी ट्रैवलर नाले में गिरने से चार लोगों की जान गई थी। खराब सड़कों और खतरनाक ढंग से ड्राइविंग के चलते तो प्रायः ही वाहन खाई में गिरते रहते हैं। वास्तव में अपने देश में कहीं पर कभी भी हादसा होने की आशंका बनी ही रहती है। ऐसा आम तौर पर सुरक्षा उपायों की अनदेखी और सतर्कता के अभाव के चलते होता है। यह कहने में हर्ज नहीं कि भारत में हर स्तर पर सार्वजनिक सुरक्षा को लेकर लापरवाही बरतने का शर्मनाक सिलसिला कायम है।

सार्वजनिक बहस का मुद्दा बनता भारत में शहरी नियोजन

यह एक भयानक तमाशा है कि क्या होता है जब राजनेता जो केवल अनुबंधों पर अपनी आंखों के साथ काम करते हैं, शासक जिन्हें पता नहीं है कि शहरी नियोजन क्या है, और ये शासक जो अपने कर्तव्यों के प्रति बेहद लापरवाह हैं, यह देखने के लिए एक साथ आते हैं कि वर्तमान महाराष्ट्र में क्या होता है।

जब भी हमारे शहरों पर कोई बड़ा संकट आता है तो भारत में शहरी नियोजन का अव्यवस्थित स्वरूप अक्सर सार्वजनिक बहस का मुद्दा बन जाता है, जैसे कि चेन्नई शहर में आई बाढ़ के बाद हुआ था। चूँकि शहरी नियोजन और इसके प्रवर्तन को आम तौर पर भारत के निष्क्रिय शहरों के लिए ज़िम्मेदार घोषित कर दिया जाता है, इसलिए आवश्यकता इस बात की है कि भारत की मौजूदा शहरी नियोजन व्यवस्था के मूलभूत तत्वों की गहन पड़ताल की जाए। हमें भारत में शहरी नियोजन के संस्थागत ढाँचे के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न पूछने होंगेः शहर की योजना बनाने का अधिकार किसके पास है? आखिर भारत के शहरी नियोजन के कानून और प्रक्रियाएँ ऐसी क्यों बनाई गई हैं? हालाँकि भारत की संवैधानिक योजना के अंतर्गत शहरी नियोजन का काम निर्वाचित स्थानीय सरकारों का है, लेकिन नियोजन की यह प्रक्रिया मुख्यतः राज्य सरकार के तहत गैर-प्रतिनिधि नौकरशाही एजेंसियों द्वारा संपन्न की जाती है। यहाँ मैं इस विसंगति के मूलभूत कारणों को उजागर करना चाहूँगा। मैं भारत के शहरी नियोजन संबंधी संस्थानों से संबंधित मूलभूत ऐतिहासिक कारणों का पता लगाना चाहूँगा ताकि यह उजागर किया जा सके कि शहरी नियोजन और ₹सुधार₹ को शहर की राजनीति से अलग रखने का औपनिवेशिक तर्क आज भी भारत में नियोजन प्रक्रियाओं को कैसे प्रभावित कर रहा है। साथ ही मैं भारतीय शहरों के नियोजन की पुराने ढंग की ऐसी परिपाटी के प्रभावों की भी जाँच करना चाहूँगा। सन् 1992 में भारत की स्थानीय शासन प्रणाली में संवैधानिक सुधारों (73वें और 74वें संशोधन के रूप में) के साथ-साथ भारी परिवर्तन भी किये गए। इन सुधारों के द्वारा ग्रामीण और शहरी स्थानीय सरकारों को ₹स्व-शासन की संस्थाओं₹ के रूप में काम करने योग्य बनाया गया। 74वें संशोधन में निर्वाचित नगर पालिकाओं को आर्थिक विकास एवं सामाजिक न्याय और 12वीं अनुसूची के तहत सूचीबद्ध विषयों के लिए योजनाएँ और स्कीमें तैयार करने और लागू करने की शक्ति प्रदान की गई है। 12 वीं अनुसूची में सूचीबद्ध विषयों के अंतर्गत पहले तीन विषय हैं, शहरी नियोजन, ज़मीन के उपयोग का विनियमन और आर्थिक एवं सामाजिक विकास।

इसके अलावा, 74 वें संशोधन के अंतर्गत 1 मिलियन से अधिक आबादी वाले महानगरीय शहरों के लिए, महानगरीय नियोजन समिति (MPC) का गठन अनिवार्य किया गया है। इस समिति में कम से कम दो-तिहाई सदस्य स्थानीय प्रतिनिधि चुनने का प्रावधान है, ताकि महानगर क्षेत्र में स्थानीय निकायों द्वारा तैयार की गई योजनाओं को शामिल करते हुए विकास की योजना तैयार की जा सके। यही कारण है कि व्यापक क्षेत्र के लिए योजना तैयार करने के लिए उत्तरदायी नगर पालिकाओं के साथ शहरी नियोजन के कार्य को भी निर्वाचित नगर पालिकाओं के साथ जोड़ दिया गया। परंतु यह विकास प्राधिकरण नगर पालिका की सरकार या नगर पालिका के बजाय राज्य सरकार के नियंत्रण में है और इसका मुख्य दायित्व भारत के अधिकांश बड़े शहरों में शहरी नियोजन ही है। विकास प्राधिकरण ऐसी सांविधिक एजेंसियाँ हैं जो अवसंरचनात्मक विकास और आवासीय परियोजनाओं के साथ-साथ नगर में शहरी नियोजन के लिए भी ज़िम्मेदार हैं। वे ऐसी नौकरशाही की एजेंसियाँ हैं, जिनमें न तो स्थानीय प्रतिनिधित्व होता है और न ही स्थानीय सरकार के प्रति किसी तरह की जवाबदेही होती है। दिल्ली विकास प्राधिकरण या बैंगलोर विकास प्राधिकरण जैसी एजेंसियाँ "मास्टर योजनाएँ" बनाती हैं, जिनके माध्यम से हर 10-20 साल में शहर में भूमि के उपयोग और विकास का विनियमन किया जाता है। भारत में शहरी नियोजन की खामी यही रही है कि एक लंबे समय से इसमें स्थानीय लोकतंत्र का अभाव रहा है। भारत की मौजूदा शहरी नियोजन प्रणाली का आधार वे योजना संस्थाएँ और कानून रहे हैं, जिनकी स्थापना साम्राज्यवादी ब्रिटिश सरकार ने सन् 1886 में बंबई में बुबोनिक प्लेग फैलने पर की थी। ब्रिटिश द्वारा निर्मित अधिकांश शहर दोहरे नगर के रूप में चलते थे। दोनों शहरों में स्पष्ट विभाजन होता था। "फ़ोर्ट" इलाके में ब्रिटिश रहते थे और "देसी" कस्बे में भारतीय रहते थे। प्लेग के प्रकोप से पहले तक ब्रिटिश मुख्यतः छावनियों में और उससे जुड़े सिविल लाइंस के इलाकों में रहते थे। लेकिन जब प्लेग ने बंबई की 6 प्रतिशत आबादी को खत्म कर दिया और शहर में व्यावसायिक गतिविधियों को ठप्प कर दिया तो साम्राज्यवादी सरकार को लगा कि उन्हें दखल देने की आवश्यकता है और समग्र रूप में एक शहर के विकास को विनियमित करना होगा। सन् 1898 में बंबई सुधार न्यास का गठन किया गया और उसके आधार पर पूरे ब्रिटिश इंडिया में इस प्रकार की विभिन्न न्यासों का गठन किया गया। बीमारियों के प्रकोप को रोकने के लिए न्यास को यह दायित्व सौंपा गया कि वे बाहरी नियोजन, नई सड़कों का जाल बिछाने, मकानों के निर्माण और भीड़-भाड़ भरे इलाकों में भीड़ को कम करने के लिए आवश्यक कदम उठाएँ। साम्राज्यवादी सरकार ने महसूस किया कि प्लेग फैलने का मुख्य कारण है, "देसी" इलाकों में भीड़-भाड़ और गंदगी होना। इसलिए उन्होंने झोपड़-पट्टियों को गिराकर उनमें सुधार लाने के लिए न्यासों को "विशिष्ट डोमेन" अधिकार प्रदान किये। बाद में नगर सुधार न्यासों की स्थापना कलकत्ता, लखनऊ, कानपुर, इलाहाबाद, दिल्ली और बैंगलोर जैसे ब्रिटिश नियंत्रण वाले विभिन्न शहरों में की गई। इन न्यासों का संचालन नगर निगमों के समानांतर स्वायत्त रूप में होता था और सन् 1882 में ब्रिटिश वायसराय लॉर्ड रिपन द्वारा जारी किये गए स्थानीय स्व-शासन के प्रस्ताव के बाद ये न्यास आंशिक तौर पर प्रतिनिधि निकाय बन गए। इन न्यासों के संचालन से यह सुनिश्चित हो गया कि साम्राज्यवादी नौकरशाही निर्वाचित नगर निगमों के दखल के बिना ही शहरी विकास के लिए आवश्यक निर्देश दे सकती थी और उन्हें विनियमित भी कर सकती थी। स्थानीय राजनीति से शहरी नियोजन की घेराबंदी की नगर सुधार न्यासों की यह प्रथा स्थायी उत्तर-साम्राज्यवादी विरासत है और बाद में ये न्यास ही विकास प्राधिकरणों के रूप में बदल गए। हर साल विकास प्राधिकरणों की बढ़ती शक्तियों को विकेंद्रित करके स्थानीय सरकार को सौंपने के संवैधानिक हस्तक्षेपों के बावजूद राज्य में निहित नौकरशाही के ढाँचे को गिराना संभव नहीं हो पाया। 74 वें संशोधन को पारित करने के लगभग तीन दशक के बाद भी शहरी नियोजन और विकास प्राधिकरण को शासित करने वाले विधायी कानूनों में ऐसा कोई परिवर्तन नहीं हुआ है जिनसे नियोजन प्रक्रियाओं को लोकतांत्रिक बनाया जा सका हो। शहरी नियोजन संबंधी अधिकांश कानून 1960 के संघ सरकार के मॉडल टाउन और कंट्री नियोजन कानून पर आधारित रहे हैं और यह कानून ही अपने-आपमें ब्रिटिश टाउन ऐंड कंट्री प्लैनिंग ऐक्ट ऑफ़ 1947 पर आधारित है। इन कानूनों से ही केंद्रीकृत और टॉप-डाउन नियोजन प्रणाली विकसित हुई है और यह प्रणाली स्थानीय सरकार से संबद्ध नहीं है और इनमें आम लोगों की भागीदारी की बहुत कम गुंजाइश है।

अशोक भाटिया

शहर और शहरी होने की दौड़ में गाँव और ग्रामीण : कितना सही, कितना गलत

आज के भारत में एक विचित्र और विरोधाभासी दृश्य सामने आता है जब हम किसी भी छोटे कस्बे या मध्यम आकार के शहर की सड़कों पर निकलते हैं। एक तरफ चौड़ी होती सड़कें हैं, बहुमंजिला इमारतें हैं, शॉपिंग मॉल हैं और स्मार्टफोन की चमकती स्क्रीनें हैं, तो दूसरी तरफ उन्हीं सड़कों पर चलते हुए वे लोग भी मिल जाते हैं जो महज कुछ वर्ष पहले तक किसी दूर-दराज़ के गाँव में रहते थे, खेत जोतते थे, पेड़ों की छाँव में बैठकर हुक्का पीते थे और रात को खुले आसमान तले सोते थे। आज वे शहर में हैं — या कम से कम शहर की परिधि में — और उनकी भाषा, उनका पहनावा, उनके सपने, यहाँ तक कि उनके खाने की आदतें भी बदल रही हैं। यह परिवर्तन न तो पूरी तरह स्वेच्छा से हुआ है और न ही पूरी तरह मजबूरी में। यह एक जटिल, बहुआयामी और कभी-कभी दर्दनाक रूप से द्वंद्वात्मक प्रक्रिया है जिसे हम 'शहरीकरण' का सरल नाम देकर आगे बढ़ जाते हैं जबकि इसके भीतर एक पूरी सभ्यता का टूटना और बनना एक साथ चल रहा होता है। यह प्रश्न कि शहर और शहरी होने की दौड़ में गाँव और ग्रामीणों का क्या हो रहा है — यह प्रश्न केवल समाजशास्त्रीय नहीं है, यह गहरे अर्थों में नैतिक और दार्शनिक भी है। जब हम किसी व्यक्ति के जीवन का मूल्यांकन इस आधार पर करने लगते हैं कि वह शहर में रहता है या गाँव में, कि वह अंग्रेज़ी बोलता है या भोजपुरी, कि वह सूट पहनता है या धोती — तो हम दरअसल उस व्यक्ति की मनुष्यता को एक सांस्कृतिक पदानुक्रम की सीढ़ियों पर तोलने की कोशिश कर रहे होते हैं। और इस तोल में, अनिवार्य रूप से, गाँव और ग्रामीण हमेशा नीचे पाए जाते हैं — कम विकसित, कम आधुनिक, कम सभ्य। यह धारणा न केवल ऐतिहासिक रूप से गलत है, बल्कि वर्तमान में भी इसके परिणाम अत्यंत विनाशकारी हैं। भारत के गाँव महज भूगोल की एक इकाई नहीं हैं। वे एक जीवन-दर्शन हैं, एक ज्ञान-परंपरा हैं, एक पारिस्थितिकी तंत्र हैं। सदियों से गाँव के किसान ने मिट्टी को पढ़ा है, मौसम को समझा है, बीज को जाना है। उसने वह ज्ञान अर्जित किया है जो किसी विश्वविद्यालय की पाठ्यपुस्तक में नहीं मिलता। एक अनुभवी किसान जब कहता है कि ₹इस साल बादल देर से आएंगे₹ तो वह केवल अंदाज़ा नहीं लगा रहा होता — वह दशकों के अनुभव से बनी एक समझ को व्यक्त कर रहा होता है जिसे पारंपरिक पारिस्थितिकीय ज्ञान कहते हैं। लेकिन शहरीकरण की इस दौड़ में इस ज्ञान को न केवल उपेक्षित किया जा रहा है, बल्कि उसे पिछड़ेपन की निशानी के रूप में देखा जा रहा है। जो व्यक्ति मोबाइल से मौसम की जानकारी लेता है उसे 'आधुनिक' कहा जाता है और जो पीपल के पत्तों की गति देखकर हवा का अंदाज़ लगाता है।

डॉ. शैलेश शुक्ला

जन सुराज का...

एस रघोत्तम

पीएफबीआर की सफलता से शुरू होगी भारत की असली चुनौती

भारत के विस्तार पर सबसे बड़ी बाधा विखंडनीय प्लूटोनियम भंडार है, विशेष रूप से 2035-2045 के बीच। वर्तमान में ब्रीडर कार्यक्रम सीमित संख्या में असुरक्षित रिएक्टरों से प्राप्त प्लूटोनियम पर निर्भर है। वहीं, भारत ने अपने सुरक्षित रिएक्टरों के लिए आयातित यूरेनियम से खर्च किया हुआ ईंधन जमा कर लिया है। यह महत्वपूर्ण प्लूटोनियम बेकार पड़ा है। अभी खत्म हुए अप्रैल की शुरुआत में भारत के प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर (उन्नत परमाणु रिएक्टर- पीएफबीआर) की सफलता ने, जो बिजली उत्पादन के दौरान खर्च किए गए ईंधन की तुलना में अधिक नया ईंधन उत्पन्न करता है, एक बहुप्रतीक्षित उपलब्धि को चिह्नित किया है। इसने 1950 के दशक में होमी जहांगीर भाभा द्वारा परिकल्पित तीन स्तरीय परमाणु कार्यक्रम के दूसरे चरण में भारत के परिचालन प्रवेश का संकेत दिया है। यह उपलब्धि बहुत बड़ी है- दशकों तक प्रौद्योगिकी से वंचित रहने और संदेह व अनिश्चितता के बावजूद भारत ने अपने वैज्ञानिकों और इंजीनियरों के दम पर दृढ़ संकल्पित होकर व्यावसायिक पैमाने पर फास्ट ब्रीडर रिएक्टर (एफबीआर) का निर्माण किया है। फिर भी हमें सोशल मीडिया और यहां तक कि मुख्यधारा के मीडिया में व्याप्त प्रचार से परे देखना होगा। पीएफबीआर अंतिम लक्ष्य नहीं है। वास्तव में यह वह बिंदु है जहां कार्यक्रम अपने सबसे कठिन चरण में प्रवेश करता है। सवाल यह है कि क्या भारत इस कार्यक्रम को देश की बढ़ती ऊर्जा सम्बन्धी जरूरतों और वैश्विक ऊर्जा परिवर्तन के लिए प्रासंगिक बनाए रखने के लिए औद्योगिक पैमाने पर तेजी से विकसित कर सकता है। भाभा के कार्यक्रम का तर्क अक्सर एक सुव्यवस्थित प्रगति के रूप में प्रस्तुत किया जाता है- चरण 1 यूरेनियम रिएक्टर प्लूटोनियम को उप-उत्पाद के रूप में

उत्पन्न करते हैं; चरण 2 एफबीआर उस प्लूटोनियम का उपयोग करके अधिक विखंडनीय पदार्थ का उत्पादन करते हैं और चरण 3 एक स्व-संचालित थोरियम चक्र पर चलता है। हमारी आज की अड़चन रिएक्टर नहीं बल्कि विखंडनीय भंडार-प्लूटोनियम है। परमाणु ऊर्जा विभाग (डीएई) के वरिष्ठ अधिकारियों के अनुमानों और हालिया बयानों के अनुसार भारत के पास पीएफबीआर और दो अन्य 500 मेगावाट के रिएक्टर, एफबीआर 1 और 2 को शुरू करने एवं चलाने के लिए पर्याप्त पृथक प्लूटोनियम है। यदि आज अंतिम स्वीकृति व निधि मिल जाती है और निर्माण कार्य सुचारू रूप से चलता है तो हम उम्मीद कर सकते हैं कि ये इकाइयां वर्ष 2035 तक चालू हो जाएंगी। हालांकि तैयार ईंधन की आपूर्ति यहीं समाप्त हो जाती है। ब्रीडर रिएक्टरों का नाम उनकी खपत से अधिक ईंधन उत्पादन करने की क्षमता के आधार पर रखा गया है लेकिन यह दर ब्रीडिंग अनुपात पर निर्भर करती है। मिश्रित ऑक्साइड (एमओएक्स) ईंधन का उपयोग करने वाले पीएफबीआर और एफबीआर 1 और 2 के लिए ब्रीडिंग अनुपात मामूली 1.03 से 1.05 है। इसके परिणामस्वरूप कूलिंग, रिप्रोसिसिंग और ईंधन में पुनः निर्माण को ध्यान में रखते हुए सिस्टम के दोगुना होने का समय लगभग 30 वर्ष है। यानी प्रत्येक रिएक्टर को एक और इकाई शुरू करने के लिए पर्याप्त अधिशेष प्लूटोनियम उत्पन्न करने में इतना समय लगेगा। इस दर पर एफबीआर कार्यक्रम का विस्तार संभव नहीं होगा। इसमें ठहराव आ जाएगा। अगले एक दशक और उससे भी अधिक समय तक यह विस्तार नए रिएक्टरों के निर्माण पर कम और भारत के प्रथम चरण के दाबयुक्त भारी जल रिएक्टरों (पीएचडब्ल्यूआर) से प्रयुक्त ईंधन के पुनर्संसाधन पर अधिक निर्भर करेगा। भारत के प्रयुक्त ईंधन में कई टन अविभाजित प्लूटोनियम मौजूद है। इस सामग्री को प्रचलन में लाना ही पहले तीन रिएक्टरों से आगे एफबीआर विस्तार की गति निर्धारित करेगा। यहां महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि बुनियादी ढांचा अभी भी इस स्तर तक नहीं पहुंच पाया है। तारापुर में एकीकृत परमाणु पुनर्चक्रण संयंत्र (इंटीग्रेटेड न्यूक्लियर रिसायकलिंग प्लांट-आईएनआरपी) क्षमता का विस्तार करेगा लेकिन इसके 2028 तक पूरा होने की उम्मीद है और इसकी उत्पादन क्षमता केवल 3-4 और सभी एफबीआर की जरूरत पूरा कर पाएगा। इस बीच, एफबीआर ईंधन के पुनर्संसाधन के लिए निर्मित कल्पक्कम स्थित फास्ट रिएक्टर फ्यूल साइकिल फैसिलिटी (एफआरएफसीएफ) में 2030 तक विलंब हो गया है। यहां तक कि परिचालन में आने पर भी इसकी क्षमता केवल प्रारंभिक तीन रिएक्टरों के लिए ही निर्धारित है। जब तक पुनर्संसाधन क्षमता में पर्याप्त विस्तार नहीं किया जाता, रिएक्टरों का अगला सेट संभवतः 2045 के बाद ही शुरू हो पाएगा और थोरियम की ओर सार्थक परिवर्तन 2060 के बाद ही संभव हो सकेगा। भारत के पास इतना समय नहीं है। दो संरचनात्मक बदलावों ने समय सीमा को कम कर दिया है।

'प्रताप' अखबार के ...

डॉ. शैलेश शुक्ला

कलम का कालजयी कारवांः हिंदी पत्रकारिता की 200 वर्षों की कालजयी कीर्ति

हिंदी पत्रकारिता के 200 वर्षों का वृत्तांत केवल एक भाषायी माध्यम की विकास गाथा नहीं है, बल्कि यह भारत के उस 'बौद्धिक पुनर्जागरण' का दस्तावेज है जिसने औपनिवेशिक दासता से लेकर लोकतांत्रिक स्वाधीनता तक की यात्रा में भारतीय जनमानस की चेतना को परिष्कृत किया है। 1826 में कलकत्ता के एक छोटे से प्रेस से 'उदन्त मार्तण्ड' के रूप में प्रस्फुटित हुई यह धारा आज वैश्विक डिजिटल परिदृश्य का एक विशाल महासागर बन चुकी है। इस यात्रा को समझने के लिए हमें उस युग की विसंगतियों और संघर्षों के साथ वर्तमान के सूचना-तंत्र के जटिल ताने-बाने का समानांतर अवलोकन करना होगा। जब पंडित युगल किशोर शुक्ल ने हिंदी पत्रकारिता का बीजारोपण किया, तब भारत में संचार का कोई व्यवस्थित ढांचा नहीं था, और हिंदी को राजदरबारी या साहित्यिक भाषा के रूप में देखा जाता था, किंतु पत्रकारिता ने उसे 'जनभाषा' के रूप में प्रतिष्ठित कर एक ऐसे वैचारिक आंदोलन को जन्म दिया, जिसने आने वाली पीढ़ियों के लिए अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का द्वार खोला। पत्रकारिता का वह प्रारंभिक युग समर्पण का युग था, जहाँ संपादक स्वयं लेखक, मुद्रक और वितरक की भूमिका निभाते थे, और उनका एकमात्र उद्देश्य सत्य की प्रतिष्ठा और समाज की कुरीतियों के विरुद्ध एक सजग प्रहरी के रूप में कार्य करना था। यह पत्रकारिता का वह गौरवपूर्ण कालखंड था जिसमें 'बनारस अखबार', 'सुधाकर', और 'हिंदी प्रदीप' जैसे प्रकाशनों ने भारतीय समाज को आत्म-मंथन के लिए विवश किया। 19वीं सदी के उत्तरार्ध में जब बंगाल नवजागरण की लहर भारत के अन्य हिस्सों में पहुंची, तब हिंदी पत्रकारिता ने उस लहर को भाषा का संबल प्रदान किया। भारतेंदु हरिश्चंद्र के समय में साहित्य और पत्रकारिता का जो अद्भुत संगम हुआ, उसने हिंदी को एक राष्ट्रीय भाषा के रूप में स्थापित करने की दिशा में निर्णायक कदम उठाए। महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा 'सरस्वती' के संपादन काल ने हिंदी भाषा को व्याकरणिक और शैलीगत परिपक्वता प्रदान की, जिससे पत्रकारिता का स्तर न केवल बढ़ा, बल्कि वह बौद्धिक विमर्श का केंद्र बन गई। यह वह समय था जब पत्रकारिता ने शिक्षा, सामाजिक सुधार, और धार्मिक पाखंडों के विरोध को अपना मुख्य एजेंडा बनाया था। पत्रकारों का वर्ग उस समय उच्च शिक्षित और त्यागी श्रेणी का था, जो अपनी जीविका के लिए पत्रकारिता नहीं, बल्कि राष्ट्र की सेवा के लिए इसे अपनाते थे। उनका लेखन तत्कालीन समाज के घावों पर मरहम भी लगाता था और शोषक वर्ग के विरुद्ध एक तार्किक चुनौती भी प्रस्तुत करता था। स्वाधीनता संग्राम के वर्षों में हिंदी पत्रकारिता ने जिस जुझारूपन का परिचय दिया, वह विश्व के पत्रकारिता इतिहास में अद्वितीय है। गांधी जी, लोकमान्य तिलक, और गणेश शंकर विद्यार्थी जैसे महान विचारकों ने पत्रकारिता को जन-आंदोलन का मुख्य अस्त्र बनाया। 'प्रताप' अखबार के पन्नों में जो वैचारिक धार थी, उसने कानपुर के श्रमिकों से लेकर देशभर के युवाओं को ब्रिटिश शासन की जड़ों को हिलाने के लिए प्रेरित किया। गणेश शंकर विद्यार्थी का व्यक्तित्व इस बात का प्रमाण था कि पत्रकारिता केवल खबरों का संकलन नहीं, बल्कि एक जीवन-दर्शन है। असहयोग और सविनय अवज्ञा आंदोलनों के दौरान हिंदी अखबारों ने सूचनाओं का संचरण ही नहीं किया, बल्कि वे स्वराज के स्वप्न को साकार करने वाले सेतु बने।

जरा हटके

तब यह प्रश्न अत्यंत ...

डॉ. शैलेश शुक्ला

मजदूर दिवस के बाद : मजदूर, मशीन और मर्म का मंथन

मजदूर दिवस बीत गया—एक ऐसा दिन, जब मंचों पर श्रम की महत्ता के गीत गाए गए, भाषणों में गरीब, किसान और मजदूर वर्ग को राष्ट्र की रीढ़ बताया गया और संवेदनाओं के शब्दों से वातावरण भर दिया गया। सरकारी सभागारों से लेकर निजी संस्थानों तक, हर जगह श्रम की गरिमा का गुणगान हुआ, तस्वीरें खिंचीं, घोषणाएँ हुईं और वादों का एक परिचित सिलसिला दोहराया गया। परंतु जैसे ही यह दिन कैलेंडर के पन्नों में सिमट गया, वही प्रश्न फिर हमारे सामने खड़ा हो गया—क्या यह सम्मान केवल एक दिन का उत्सव है, या वास्तव में उन हाथों की तकलीफों को समझने का प्रयास, जो रोज़ अपनी मेहनत से इस देश की नींव मजबूत करते हैं? वास्तविकता यह है कि मंचों की चमक-दमक और जमीनी हकीकत के बीच एक गहरी खाई अब भी मौजूद है। जिन मजदूरों के नाम पर योजनाएँ बनती हैं, वे आज भी असंगठित क्षेत्र में असुरक्षित काम करने को मजबूर हैं; जिन किसानों को 'अन्नदाता' कहा जाता है, वे कर्ज और अनिश्चितताओं के बोझ तले दबे हैं। ऐसे में मजदूर दिवस का यह औपचारिक उत्सव हमें आत्ममंथन के लिए विवश करता है—क्या हम सच में श्रम का सम्मान कर रहे हैं, या केवल शब्दों में उसकी प्रतिष्ठा गढ़ रहे हैं? आज जब हम अंतरराष्ट्रीय मजदूर दिवस के व्यापक संदर्भ में श्रम, उत्पादन और मानव गरिमा के प्रश्नों पर विचार करते हैं, तब यह स्पष्ट दिखाई देता है कि हम एक ऐसे ऐतिहासिक संक्रमण काल से गुजर रहे हैं जहाँ तकनीक केवल सहायक शक्ति नहीं रह गई है, बल्कि वह स्वयं निर्णयकारी और संरचनात्मक भूमिका निभाने लगी है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता का उदय और उसका तीव्र विस्तार इस परिवर्तन का सबसे प्रमुख संकेत है। यह परिवर्तन केवल मशीनों के परिष्कार का नहीं, बल्कि उस सोच के बदलाव का है जिसके माध्यम से मनुष्य कार्य, उत्पादकता और अपनी उपयोगिता को समझता आया है। अब तक श्रम को मानव अस्तित्व की केंद्रीय धुरी माना जाता रहा है, क्योंकि श्रम ही वह माध्यम था जिसके द्वारा व्यक्ति न केवल जीविका अर्जित करता था, बल्कि अपनी पहचान और सामाजिक प्रतिष्ठा भी निर्मित करता था। किंतु आज जब निर्णय, विश्लेषण और सृजन के क्षेत्र में भी तकनीकी हस्तक्षेप बढ़ रहा है, तब यह प्रश्न अत्यंत गंभीर हो उठता है कि क्या भविष्य में श्रम का वही नैतिक और सामाजिक महत्व बना रहेगा, या फिर हमें इसकी नई परिभाषा गढ़नी होगी। रोजगार के संदर्भ में यह परिवर्तन बहुआयामी है और इसके प्रभाव को केवल संख्यात्मक दृष्टि से नहीं समझा जा सकता। यह सही है कि नई तकनीकें कुछ क्षेत्रों में नए अवसर पैदा करती हैं, लेकिन यह भी उतना ही सत्य है कि वे पारंपरिक कार्यों को तेजी से अप्रासंगिक बना देती हैं। आज की स्थिति में सबसे बड़ी चुनौती यह है कि रोजगार का स्वरूप स्थायित्व से अस्थायित्व की ओर बढ़ रहा है। स्थायी नौकरियों का स्थान अनुबंध आधारित और असंगठित कार्य ले रहे हैं, जहाँ सुरक्षा, सामाजिक लाभ और दीर्घकालिक स्थिरता का अभाव होता है। यह स्थिति श्रमिकों के लिए केवल आर्थिक असुरक्षा ही नहीं, बल्कि मानसिक तनाव और सामाजिक अनिश्चितता का भी कारण बनती है। इसके साथ ही यह भी देखने को मिल रहा है कि उच्च कौशल वाले और तकनीकी रूप से दक्ष लोगों के लिए अवसर बढ़ रहे हैं जबकि कम कौशल वाले श्रमिकों के लिए विकल्प सीमित होते जा रहे हैं। इस प्रकार एक ऐसा द्वंद्व उत्पन्न हो रहा है जहाँ अवसरों का विस्तार और संकुचन एक साथ घटित हो रहा है और यह द्वंद्व भविष्य में और अधिक तीव्र हो सकता है। कौशल के क्षेत्र में जो परिवर्तन हो रहा है, वह इस पूरे विमर्श का सबसे निर्णायक पक्ष है। पारंपरिक शिक्षा प्रणाली, जो एक निश्चित अवधि में ज्ञान प्रदान करने पर आधारित रही है, अब इस चुनौती के सामने अपर्याप्त सिद्ध हो रही है। आज आवश्यकता इस बात की है कि व्यक्ति निरंतर सीखने की क्षमता विकसित करे और बदलती परिस्थितियों के अनुसार स्वयं को ढाल सके। इसका अर्थ यह है कि शिक्षा को एक स्थिर प्रक्रिया के रूप में नहीं, बल्कि एक सतत यात्रा के रूप में देखा जाना चाहिए। इसके साथ ही यह भी आवश्यक है कि शिक्षा और प्रशिक्षण के अवसरों तक समान पहुंच सुनिश्चित की जाए, अन्यथा समाज में एक नया वर्ग विभाजन उत्पन्न होगा, जहाँ कुछ लोग तकनीकी प्रगति के साथ आगे बढ़ेंगे और शेष लोग पीछे छूट जाएंगे। यह विभाजन केवल आर्थिक नहीं होगा, बल्कि यह सामाजिक और सांस्कृतिक असमानताओं को भी गहरा करेगा, जिससे समाज में तनाव और असंतोष की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। असमानता का प्रश्न इस पूरे परिवर्तन का सबसे संवेदनशील और दीर्घकालिक प्रभाव डालने वाला पहलू है। तकनीकी प्रगति के लाभ समान रूप से वितरित नहीं होते, बल्कि वे उन लोगों के हाथों में केंद्रित हो जाते हैं जिनके पास संसाधन, ज्ञान और नियंत्रण की शक्ति होती है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता के संदर्भ में यह प्रवृत्ति और अधिक स्पष्ट रूप से दिखाई देती है, क्योंकि इसके विकास और उपयोग में बड़ी कंपनियों और शक्तिशाली संस्थाओं की प्रमुख भूमिका होती है। इससे आय और अवसरों के बीच की खाई बढ़ने का खतरा है, जो सामाजिक असंतुलन को जन्म दे सकता है। यदि इस प्रवृत्ति को नियंत्रित नहीं किया गया, तो यह केवल आर्थिक असमानता तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि यह राजनीतिक और सामाजिक अस्थिरता का कारण भी बन सकता है। इसलिए यह आवश्यक है कि हम तकनीकी प्रगति को केवल आर्थिक लाभ के दृष्टिकोण से न देखें, बल्कि इसके सामाजिक प्रभावों को भी गंभीरता से समझें और उन्हें संतुलित करने के उपाय खोजें। यह भी महत्वपूर्ण है कि हम इस परिवर्तन के नैतिक और दार्शनिक आयामों पर विचार करें। जब मशीनें निर्णय लेने लगती हैं और मानव हस्तक्षेप कम होता जाता है, तब यह प्रश्न उठता है कि जिम्मेदारी और उत्तरदायित्व का निर्धारण कैसे होगा। यदि किसी तकनीकी प्रणाली द्वारा लिया गया निर्णय गलत सिद्ध होता है।

दिल्ली आईपीएल में लगातार तीन हार के बाद जीती

राजस्थान को 7 विकेट से हराया, राहुल-निसांका की फिफ्टी, स्टार्क को 3 विकेट

जयपुर, एजेंसी

दिल्ली कैपिटल्स को IPL के मौजूदा सीजन में लगातार तीन हार के बाद जीत मिली है। टीम ने शुक्रवार को राजस्थान रॉयल्स को 7 विकेट से हराया। जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में दिल्ली ने 226 रन का टारगेट 19.1 ओवर में 3 विकेट पर चेज कर दिया। टॉस जीतकर बैटिंग करते हुए राजस्थान ने 20 ओवर में 6 विकेट पर 225 रन बनाए। दिल्ली की ओर से ओपनर्स ने 110 रन की साझेदारी की। इस साझेदारी के सहारे दिल्ली ने IPL में अपना सबसे बड़ा रन चेज किया। मैच का स्कोरबोर्ड दिल्ली की ओर से केएल राहुल ने 40 बॉल पर 75 रन की पारी खेली। इस पारी में 6 चौके और 5 छक्के शामिल रहे। राहुल के ओपनिंग पार्टनर पाथुम निसांका ने 33 बॉल पर 6 चौके और 3 छक्के के सहारे 62 रन बनाए। दिल्ली- केएल राहुल, पाथुम निसांका, समीर रिजवी, नीतीश राणा, ट्रिस्टन स्टब्स, अक्षर पटेल (कप्तान), आशुतोष शर्मा,

काइल जैमिसन, मिचेल स्टार्क, 18वें ओवर में दिल्ली ने 200 रन का आंकड़ा हासिल कर लिया। आशुतोष शर्मा ने तुषार देशपांडे की दूसरी बॉल पर चौका लगाकर टीम को 200 पार पहुंचाया। 14वें ओवर में दिल्ली ने 150 रन का आंकड़ा पार कर लिया है। नीतीश राणा ने नांद्रे बर्गर के ओवर की पहली बॉल पर छक्का लगाया। इसी छक्के से टीम का स्कोर 150 पार हुआ। इसी ओवर में राहुल ने बर्गर की चौथी बॉल पर छक्का लगाया और राणा के साथ फिफ्टी पार्टनरशिप पूरी की। 12वें ओवर में रवींद्र जडेजा ने 18 रन खर्च कर लिए। नीतीश राणा ने पहली बॉल पर छक्का लगाया। उसके बाद केएल राहुल ने तीसरी बॉल पर शानदार सिक्स लगाया। फिर राणा ने आखिरी बॉल पर छक्का

मिचेल स्टार्क ने 3 विकेट झटके

दिल्ली की ओर से सीजन का पहला मैच खेल रहे मिचेल स्टार्क ने 3 विकेट झटके। काइल जैमिसन, अक्षर पटेल और टी नटराजन को एक-एक विकेट मिला। राजस्थान- यशस्वी जायसवाल, वैभव सूर्यवंशी, ध्रुव जुरेल (विकेटकीपर), रियान पराग (कप्तान), डोनोवन फरेरा, रवींद्र जडेजा, शुभम दुबे, जोफ्रा आर्चर, रवि बिश्नोई, नांद्रे बर्गर और बृजेश शर्मा। इम्पैक्ट प्लेयरः तुषार देशपांडे।

आर्चर ने केएल राहुल को कैच आउट कराया

16वें ओवर की दूसरी बॉल पर केएल राहुल 75 रन बनाकर आउट हुए। उन्हें जोफ्रा आर्चर ने डोनेवान फरेरा के हाथों कैच कराया। 15वें ओवर की तीसरी बॉल पर नीतीश राणा 33 रन बनाकर आउट हुए। उन्हें तुषार देशपांडे ने विकेटकीपर ध्रुव जुरेल के हाथों कैच कराया। इसी के साथ फिफ्टी पार्टनरशिप ब्रेक हुई।

लगाया। 10वें ओवर की तीसरी बॉल पर दिल्ली ने पहला विकेट गंवाया। यहां पर पाथुम निसांका 33 बॉल पर 62 रन बनाकर आउट हुए। उन्हें रवींद्र जडेजा ने LBW किया। यहां निसांका ने रिव्यू भी लिया, लेकिन अंपायर्स का फैसला नहीं बदला। इसी के साथ 110 रन की ओपनिंग पार्टनरशिप ब्रेक हो गई। 9वें ओवर में रवि बिश्नोई ने 20 रन खर्च कर लिए। केएल राहुल ने उनकी बॉल पर दो छक्के और एक चौके के सहारे 20 रन बनाए।

आखिरी ओवर में दिल्ली को 5 रनों की जरूरत थी। आशुतोष शर्मा ने बृजेश शर्मा की पहली बॉल पर चौका लगा दिया। इसके बाद बृजेश ने नो बॉल डाल दी। इससे दिल्ली को 7 विकेट की जीत मिली। कुलदीप यादव और टी नटराजन। इम्पैक्ट प्लेयरः अभिषेक पोरेल, विप्रज निगम और मुकेश कुमार।

कप्तान रियान पराग शतक चूके

कप्तान रियान पराग ने 90 रन की पारी खेली। 50 बॉल की पारी में रियान ने 8 चौके और 5 छक्के लगाए। उन्होंने ध्रुव जुरेल के साथ शतकीय साझेदारी की। जुरेल ने 42 रन बनाए। आखिरी डोनोवान फरेरा ने 14 बॉल पर 6 छक्कों के सहारे नाबाद 47 रन बनाए।

7 साल के इशांक सिंह का कारनामा

10 घंटे में 29 किलोमीटर का 'पाक स्ट्रेट' तैरकर पार किया

रांची, एजेंसी

रांची के रहनेवाले 7 साल के इशांक सिंह ने महज विश्व रिकॉर्ड बना दिया है। उन्होंने श्रीलंका के तलाईमन्नार से भारत के धनुषकोडी (तमिलनाडु) तक 29 किलोमीटर का खतरनाक 'पाक स्ट्रेट' का रास्ता 9 घंटे 50 मिनट में तैरकर पार किया। उन्होंने 30 अप्रैल 2026 को यह उपलब्धि हासिल की। इशांक अब 'पाक स्ट्रेट' का समुद्री रास्ता पार करने वाले दुनिया के सबसे कम उम्र के स्विमर बन गए हैं। यूनिवर्सल रिकॉर्ड्स फोरम ने उन्हें 'यंगेस्ट एंड फास्टेस्ट पाक स्ट्रेट स्विमर' का विश्व रिकॉर्ड सर्टिफिकेट भी दिया है। इशांक रांची के धुर्वा डैम में रोजाना 4 से 5 घंटे की प्रैक्टिस करते थे। उनकी ट्रेनिंग कोच अमन कुमार जायसवाल और बजरंग कुमार के

गाइडेंस में हुई। पाल्क स्ट्रेट भारत और श्रीलंका के बीच स्थित है, जहां तेज धाराएं और समुद्री जानवरों का खतरा रहता है। इसके बावजूद उन्होंने पूरा रास्ता तय किया। इशांक रांची के डीएवी श्यामली स्कूल में तीसरी कक्षा के छात्र हैं। स्कूल प्रिंसिपल ने उनकी उपलब्धि पर गर्व जताया है। उन्होंने इशांक के उज्ज्वल भविष्य की कामना की और इसे स्कूल, रांची और पूरे देश के लिए गर्व का पल बताया है।

फास्ट न्यूज

पंजाबी सिंगर दिलजीत ने खालिस्तानियों को भगाया

जालंधर। पंजाबी और बॉलीवुड सिंगर दिलजीत दोसांझ ऑरा वर्ल्ड टूर के दौरान अमेरिका के कैलगरी में शो में खालिस्तानियों पर भड़क गए। दिलजीत ने पोस्टर दिखा रहे खालिस्तानी समर्थकों को स्टेज से ही जवाब दिया। अपने किसी शो में दिलजीत पहली बार इतने गुस्से में दिखे। दिलजीत ने सिद्धू मूसेवाला स्टाइल में अपनी जांघ पर थापी देते हुए कहा कि जिसने आना है मैदान में आ जाए।

बंद पड़े पीएफ अकाउंट ट्रैक करने आएगा 'ई-प्राप्ति' पोर्टल

नई दिल्ली। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) के लाखों सब्सक्राइबर्स और पेंशनर्स के लिए दो बड़ी खबरें सामने आई हैं। लंबे समय से कम पेंशन की शिकायत कर रहे लोगों की मांग पर सरकार अब एंप्लॉई पेंशन स्कीम (EPS-95) के तहत मिनिमम पेंशन बढ़ाने पर विचार कर रही है। इसके साथ ही, EPFO ने उन लोगों के लिए 'ई-प्राप्ति' नाम का एक नया पोर्टल लाने की घोषणा की है, जिनके पुराने PF अकाउंट्स बंद हैं या इन-एक्टिव पड़े हैं। इस पोर्टल की मदद से बिना UAN नंबर वाले लोग भी अपना फंसा हुआ पैसा निकाल सकेंगे। वर्तमान में EPS-95 स्कीम के तहत रिटायरमेंट के बाद मेंबर्स को मिनिमम 1000 प्रति महीना पेंशन मिलती है। पेंशनर्स एसोसिएशन और लेबर यूनियंस का कहना है कि आज की महंगाई के दौर में यह रकम बेहद कम है। इनकी मांग है कि इसे बढ़ाकर कम से कम 7500 किया जाए।

सामंथा ने लॉन्च किया टॉक्सिन फ्री परफ्यूम

मुंबई। फिल्म स्टार्स लंबे समय से परफ्यूम ब्रांड्स का प्रचार करते रहे हैं, लेकिन अब वे खुद इस बिजनेस में उतर रहे हैं और अपने-अपने तरीके से फैंस से जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं। रणबीर कपूर ने पिछले साल 'ARKS' नाम से परफ्यूम लॉन्च किया। इसमें रणबीर ने ऑनलाइन स्ट्रेटजी अपनाई। कंपनी ने स्विगी इंस्टामार्ट से पार्टनरशिप की और इसे क्विक कॉमर्स पर उपलब्ध कराया।

फिल्म हेरा फेरी के राइट्स को लेकर फ्रॉड का केस

फिरोज नाडियाडवाला का दावा-₹4.5 लाख में खरीदे राइट्स

मुबंई, एजेंसी

फिल्म प्रोड्यूसर फिरोज नाडियाडवाला ने साल 2000 में रिलीज हुई फिल्म हेरा फेरी के कॉपीराइट और रीमेक राइट्स को लेकर मुंबई के अंबोली पुलिस स्टेशन में फ्रॉड की शिकायत दर्ज कराई है। इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक, नाडियाडवाला ने शिकायत में कहा कि विवाद साल 1989 की मलयालम फिल्म रामजी राव स्पीकिंग से जुड़ा है, जिस पर हेरा फेरी आधारित थी। उन्होंने दावा किया कि साल 2000 में उन्होंने सुरेश कुमार सिंघल से 4.5 लाख रुपए में कुछ रीमेक राइट्स कानूनी रूप से खरीदे थे। शिकायत में कहा गया कि फिल्म रिलीज से सात दिन पहले कुछ लोगों ने दबाव बनाकर उनसे पैसे ऐंठने की कोशिश की। नाडियाडवाला के अनुसार, उन्हें

भारी इन्वेस्टमेंट और संभावित नुकसान के डर से पेमेंट करना पड़ा, जबकि कोर्ट ने उनके पक्ष में स्टे ऑर्डर दिया था। नाडियाडवाला ने यह भी आरोप लगाया कि 2022 में ओरिजिनल फिल्म से जुड़े पक्षों ने पहले से बिके राइट्स को दोबारा बेच दिया। जिसमें फिर हेरा फेरी को गैर-कानूनी बताया गया और 60 लाख रुपए के साथ फिल्म के मुनाफे में 25% हिस्सेदारी की मांग की गई।

बिग बॉस 17 के विजेता मुनव्वर फारुकी बने पिता, घर आई बेटी

सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए दी खुशखबरी, सेलेब्स ने दी बधाई

मुबंई, एजेंसी

टीवी शो बिग बॉस 17 के विनर मुनव्वर फारूकी और उनकी पत्नी महजबीन को एक बेटी हुई है। यह जानकारी मुनव्वर ने सोशल मीडिया पर शेयर की। मुनव्वर ने शुक्रवार को अपने ऑफिशियल इंस्टाग्राम अकाउंट पर पत्नी और नवजात बेटी की तस्वीरें शेयर कीं। हालांकि, उन्होंने तस्वीरों में चेहरों को पब्लिक नहीं किया। पोस्ट के साथ मुनव्वर ने लिखा, 'घर में बरकत आई। धन्य महसूस कर रहा हूं। अल्हम्दुलिल्लाह। दुआओं में खास याद रखना!' जैसे ही यह पोस्ट सामने आई, कई सेलेब्स ने कपल को बधाई दी। वरुण धवन, जन्नत जुबैर, मिस्टर फैजू, रीम शेख और अली गोनी ने शुभकामनाएं दीं। मुनव्वर ने मई 2024 में मेकअप आर्टिस्ट महजबीन कोटवाला से शादी की थी। यह उनकी दूसरी शादी थी, जिसे प्राइवेट रखा गया था और उस समय ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं की थी। फराह खान के व्लॉग में मुनव्वर ने अपनी दूसरी शादी के फैसले पर बात करते हुए कहा था।

मुनव्वर ने यह भी बताया था कि महजबीन की एक 10 साल की बेटी है और दोनों का इमोशनल कनेक्शन जल्दी हो गया था। उन्होंने मिलने के अगले दिन ही शादी के लिए प्रपोज कर दिया था।

2024 में की थी दूसरी शादी

गौरतलब है कि मुनव्वर ने मई 2024 में मेकअप आर्टिस्ट महजबीन कोटवाला से दूसरी शादी की थी। यह शादी काफी निजी रखी गई थी और उस समय इसकी आधिकारिक घोषणा नहीं की गई थी। एक व्लॉग में बातचीत के दौरान मुनव्वर ने बताया था कि उन्होंने यह फैसला अपने बेटे मिखाइल के लिए लिया था।

जर्मनी से नाराज ट्रम्प ने 5000 सैनिक वापस बुलाए

जर्मन चांसलर ने कहा था- ईरान ने अमेरिका की बेइज्जती की, अमेरिका की प्लानिंग भी बेकार

वॉशिंगटन, एजेंसी

अमेरिका ने जर्मनी से करीब 5,000 सैनिक हटाने का फैसला किया है। अमेरिकी रक्षा मंत्रालय के मुताबिक यह प्रक्रिया अगले 6 से 12 महीनों में पूरी होगी। यह कदम सीधे तौर पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प और जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज के बीच बयानबाजी के बाद सामने आया है। मर्ज ने पिछले महीने एक कार्यक्रम में कहा था कि अमेरिका के पास कोई अच्छी प्लानिंग नहीं है। उसे पता ही नहीं है कि वह इस जंग से बाहर कैसे निकलेगा। उन्होंने कहा कि ईरान बातचीत को टालने में माहिर है और अमेरिका को बिना नतीजे के इस्लामाबाद तक आना-जाना पड़ा। इससे अमेरिका को ईरान के सामने अपमानित होना पड़ा। इससे ट्रम्प नाराज हो गए थे। उन्होंने मर्ज को लेकर कहा कि वे बहुत खराब काम कर रहे हैं। उनको लगता है कि ईरान के पास परमाणु हथियार होना अच्छी बात है। उन्हें हकीकत की समझ नहीं है।

अमेरिका के जर्मनी में सैन्य ठिकाने क्यों हैं?

जर्मनी में अमेरिकी सेना की मौजूदगी 1945 से शुरू हुई, जब नाजी जर्मनी की हार के बाद अमेरिका ने वहां कब्जा कर लिया था। दूसरे विश्व युद्ध के तुरंत बाद वहां करीब 16 लाख अमेरिकी सैनिक तैनात थे, हालांकि 1 साल के बाद वहां 3 लाख सैनिक रह गए। शुरुआत में उनका काम जर्मनी के अमेरिकी कंट्रोल वाले हिस्से को संभालना और नाजीकरण खत्म करना था। लेकिन बाद में शीत युद्ध शुरू होने के साथ ही अमेरिका का मकसद बदल गया और जर्मनी को सोवियत संघ के खिलाफ एक मजबूत रक्षा दीवार बनाया गया। 1949 में नाटो बनने के बाद, अमेरिका के ये सैन्य ठिकाने स्थायी हो गए। इनका मकसद पश्चिम जर्मनी को मजबूत बनाना और सोवियत संघ के मुकाबले में खड़ा करना था।

सोवियत संघ कमजोर हुआ तो सैनिक लौटे

1989 में बर्लिन की दीवार गिरने और 1991 में सोवियत संघ के टूटने के बाद अमेरिका ने अपनी मौजूदगी काफी कम कर दी, लेकिन पूरी तरह हटाई नहीं। आज की स्थिति में, यूरोप में अमेरिका के करीब 68,000 सैनिक तैनात हैं, जिनमें से 36 हजार से ज्यादा सिर्फ जर्मनी में हैं। ये सैनिक 20 से 40 अलग-अलग बेस में फैले हुए हैं। स्टुटगार्ट में यूरोप और अफ्रीका के लिए अमेरिकी कमांड हेडक्वार्टर है, जहां से पूरे क्षेत्र में सैन्य ऑपरेशन कंट्रोल होते हैं।

■ जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प

एक्सपर्ट्स- इस फैसले से नाटो की एकता कमजोर हो सकती है

सुरक्षा एक्सपर्ट्स के मुताबिक, अमेरिका जर्मनी से अपने सैनिक हटाता है तो इसके बड़े असर हो सकते हैं। इससे नाटो की एकता कमजोर पड़ सकती है, खासकर ऐसे वक्त में जब दुनिया में पहले ही तनाव बढ़ा हुआ है। साथ ही इससे ये संदेश जा सकता है कि अमेरिका अब यूरोप की सुरक्षा को लेकर उतना गंभीर नहीं है, जिसका फायदा रूस जैसे देश उठा सकते हैं। अमेरिकी संसद में भी इस फैसले की आलोचना हो रही है। कई नेताओं ने इसे लापरवाही भरा बताया है और कहा है कि इससे यूरोप में अमेरिका की पकड़ कमजोर हो सकती है। सीनेटर जैक रीड ने कहा कि यह कदम दिखाता है कि अमेरिका अपने सहयोगियों के साथ कमिटमेंट को राष्ट्रपति के मूड के हिसाब से बदल रहा है। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर यह फैसला नहीं रोका गया, तो इससे रिश्तों और देश की सुरक्षा पर लंबे समय तक बुरा असर पड़ सकता है।

ट्रम्प ने यूरोपीय यूनियन की कार-ट्रकों पर 25% टैरिफ लगाया

कहा- व्यापार समझौते का पालन नहीं कर रहे, छूट चाहिए तो अमेरिका में मैन्युफैक्चरिंग करो

वॉशिंगटन, एजेंसी

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने शुक्रवार को घोषणा की है कि अगले हफ्ते से यूरोपीय संघ (EU) से आने वाली कारों और ट्रकों पर टैरिफ बढ़ाकर 25% कर दिया जाएगा। ट्रम्प का कहना है कि यूरोपीय संघ पहले से तय व्यापार समझौते का पालन नहीं कर रहा है, इसलिए यह फैसला लिया गया है। हालांकि अगर यूरोपीय कंपनियां अमेरिका में ही कार और ट्रक बनाएंगी, तो उन पर कोई टैक्स नहीं लगाया जाएगा। ट्रम्प के मुताबिक, इस समय अमेरिका में कई नई ऑटोमोबाइल और ट्रक फैक्ट्रियां बन रही हैं, जिनमें 100 बिलियन डॉलर से ज्यादा का निवेश हो रहा है। उन्होंने दावा किया कि अमेरिका में इस तरह का निवेश और विकास पहले कभी नहीं देखा गया। इन फैक्ट्रियों में अमेरिकी लोगों को रोजगार मिलेगा। ट्रम्प जिस व्यापार समझौते की बात कर रहे हैं वो उनके और यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयेन के बीच

पिछले साल जुलाई में हुआ था। इस समझौते को 'टर्नबेरी एग्रीमेंट' कहा जाता है, जिसका नाम स्कॉटलैंड में ट्रम्प के गोल्फ कोर्स के नाम पर रखा गया है। इस समझौते का मकसद अमेरिका और EU के बीच बढ़ते व्यापारिक तनाव को कम करना था। इस डील के तहत दोनों पक्षों ने आपसी व्यापार को संतुलित करने और टैरिफ विवाद को कम करने पर सहमति जताई थी। समझौते के मुताबिक, EU से अमेरिका आने वाले अधिकांश सामानों पर 15% टैरिफ तय किया गया था। यह बड़ा फैसला माना गया था, क्योंकि इससे पहले ट्रम्प प्रशासन 30% तक टैरिफ लगाने की चेतावनी दे चुका था।

घटी : चांदी की कीमत 3389 कम होकर 2.40 लाख किलो हुई, सोना 1216 सस्ता हुआ

इस हफ्ते सोने-चांदी में गिरावट रही

नई दिल्ली, एजेंसी

इस हफ्ते सोने-चांदी के दाम में गिरावट रही। सोना हफ्तेभर में 1,216 रुपए गिरकर 1,50,263 रुपए प्रति 10 ग्राम पर आ गया। इससे पहले ये बीते हफ्ते यानी 25 अप्रैल को 1,51,479 रुपए पर था। वहीं, चांदी 2,43,720 किलो से गिरकर 2,40,331 रुपए पर पहुंच गई है। यानी इसकी कीमत 3,389 रुपए कम हुई। चांदी के दाम में भी गिरावट देखने को मिली है। यह 3,389 रुपये घटकर 2,40,331 रुपये प्रति किलोग्राम पर पहुंच गई है, जो पिछले सप्ताह 2,43,720 रुपये प्रति किलोग्राम थी। विशेषज्ञों के अनुसार, अंतरराष्ट्रीय बाजार के रुझान और डॉलर की मजबूती का असर घरेलू बाजार में दिख रहा है। निवेशकों के रुख में बदलाव के चलते कीमती धातुओं की कीमतों में यह गिरावट देखी गई है। बाजार विशेषज्ञों का मानना है कि वैश्विक स्तर पर डॉलर की मजबूती और ब्याज दरों को लेकर अनिश्चितता के कारण निवेशकों का रुख बदल रहा है। जब डॉलर मजबूत होता है, तो सोने जैसी कीमती धातुओं में निवेश कम होता है, जिससे कीमतों पर दबाव पड़ता है।

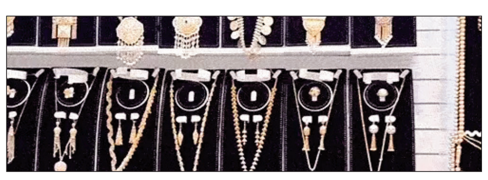

ज्वेलर्स से सोना खरीदते समय इन 2 बातों का रखें ध्यान

1. सर्टिफाइड गोल्ड ही खरीदेंः हमेशा ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड (BIS) का हॉलमार्क लगा हुआ सर्टिफाइड गोल्ड ही खरीदें। ये नंबर अल्फान्यूमेरिक यानी कुछ इस तरह से हो सकता है- AZ4524। हॉलमार्किंग से पता चलता है कि सोना कितने कैरेट का है।

2. कीमत क्रॉस चेक करेंः सोने का सही वजन और खरीदने के दिन उसकी कीमत कई सोर्सेज (जैसे इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन की वेबसाइट) से क्रॉस चेक करें। सोने का भाव 24 कैरेट, 22 कैरेट और 18 कैरेट के हिसाब से अलग-अलग होता है।

असली चांदी की पहचान करने के 4 तरीके

- ■ मैग्नेट टेस्टः असली सिल्वर चुंबक से नहीं चिपकती। अगर चिपक जाए तो फेक है।
- ■ आइस टेस्टः सिल्वर पर बर्फ रखें। असली सिल्वर पर बर्फ तेजी से पिघलती है।
- ■ स्मेल टेस्टः असली सिल्वर में गंध नहीं होती। फेक में कॉपर जैसी गंध आती है।
- ■ क्लॉथ टेस्टः चांदी को सफेद कपड़े से रगड़ें। अगर काला निशान आए तो असली है।

अंतरराष्ट्रीय बाजार के रुझानों का सीधा असर भारतीय सर्राफा बाजार पर पड़ा है। मांग में कमी और निवेशकों की सतर्कता के कारण कीमतों में गिरावट आई है। हालांकि, शादी-ब्याह के सीजन और त्योहारों के दौरान मांग बढ़ने पर कीमतों में फिर उछाल देखने को मिल सकता है।

48 घंटे में दो पायलटों की हार्ट अटैक से मौत

नई दिल्ली। दो पायलट्स की हार्ट अटैक से मौत के बाद देश में कॉमर्शियल पायलट्स की थकान और उनके ड्यूटी के घंटों को लेकर विवाद बढ़ गया है। द एयरलाइन पायलट्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (DGCA) को पत्र लिखकर फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिटेशन (FDTL) नियमों को पूरी तरह सख्ती से लागू करने की मांग की है। एसोसिएशन ने बताया कि पायलट्स का कहना है कि एयरलाइंस को नियमों में बार-बार दी जा रही छूट सुरक्षा और क्रू की सेहत के साथ समझौता है। पायलट्स एसोसिएशन ने DGCA प्रमुख वीर विक्रम यादव और नागरिक उड्डयन सचिव समीर कुमार सिन्हा को लिखे लेटर में बताया कि, बाली (इंडोनेशिया) में 29 अप्रैल को रेस्ट पीरियड के दौरान एअर इंडिया के एक पायलट की हार्ट अटैक से मौत हो गई। उन्होंने 28 अप्रैल को दिल्ली से बाली की फ्लाइट ऑपरेट की थी। वहीं, 30 अप्रैल को बेंगलुरु में ट्रेनिंग सेशन के दौरान अकासा एयर के एक पायलट (उम्र 40-45 साल) की भी हार्ट अटैक से मौत हो गई। एसोसिएशन का कहना है कि 45 साल से कम उम्र के पायलट्स की ये मौतें काम के बढ़ते दबाव और थकान की ओर इशारा करती हैं।

आपके बच्चे को लखपति बनाएगा पीपीएफ अकाउंट

अपने बच्चे के नाम खुलवाएं ये अकाउंट, जानें इसको लेकर क्या हैं नियम

नई दिल्ली, एजेंसी

अगर आप बच्चे के नाम पर निवेश शुरू करने का प्लान बना रहे हैं तो पब्लिक प्रॉविडेंट फंड (PPF) स्कीम में निवेश कर सकते हैं। इस स्कीम में अभी 7.1% सालाना ब्याज दिया जा रहा है। आप अपने बच्चे के नाम पर PPF अकाउंट खोलकर उसके लिए आसानी से लाखों का फंड तैयार कर सकते हैं। लेकिन इसके कुछ नियम हैं। हम आपको उन नियमों के बारे में बता रहे हैं एक व्यक्ति अपने नाम पर केवल एक ही PPF अकाउंट खुलवा सकता है। हालांकि व्यक्ति अपने PPF अकाउंट के अलावा नाबालिग बच्चे के नाम पर एक अन्य PPF खाता खुलवा सकता है। लेकिन यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि एक अभिभावक (गार्जियन) एक ही बच्चे के नाम पर PPF खाता खोल सकता

है। नियमों के मुताबिक, अगर किसी के दो बच्चे हैं तो एक नाबालिग बच्चे का PPF अकाउंट मां और दूसरे का पिता खुलवा सकता है। नाबालिग के PPF अकाउंट के लिए भी एक वित्त वर्ष में कम से कम 500 और अधिकतम 1.5 लाख रुपए की डिपॉजिट लिमिट लागू है। लेकिन अगर मां-पिता का खुद का PPF अकाउंट भी है तो उनके खुद के अकाउंट और नाबालिग के PPF अकाउंट दोनों को मिलाकर अधिकतम डिपॉजिट लिमिट 1.5 लाख रुपए सालाना ही रहेगी। नाबालिग बच्चे के 18 साल का हो जाने के बाद अकाउंट का स्टेटस माइनर से मेजर करने के लिए ऐप्लिकेशन देनी होगी। इसके बाद बालिग हो चुका बच्चा अपना अकाउंट खुद से हैंडल कर सकता है। PPF अकाउंट 15 साल में मैच्योर होता है। आप चाहे तो मैच्योरिटी के बाद पूरा पैसा निकाल सकते हैं। हालांकि अगर आपको पैसे की जरूरत नहीं है तो इसे 5-5 साल के लिए बढ़ाया जा सकता है। PPF इनकम टैक्स की EEE कैटेगरी में आती है। यानी योजना में किए गए पूरे निवेश पर आपको टैक्स छूट का लाभ मिलता है। साथ ही इस योजना में निवेश से मिलने वाले ब्याज और निवेश की पूरी राशि पर भी किसी तरह का टैक्स नहीं देना होता। इस स्कीम के जरिए अगर आप हर महीने 1 हजार रुपए निवेश करते हैं।

लखनऊ डीएम के सामने महिला बेहोश

समाधान दिवस में गश खाकर गिरी, जेठ ने हिस्से की जमीन कब्जा ली थी

तमसा संकेत, एजेंसी

लखनऊ। लखनऊ DM विशाख जी के सामने शनिवार को एक महिला बेहोश हो गई। वह समाधान दिवस में जमीन विवाद की शिकायत लेकर आई थी। महिला शिकायत करते हुए रोने लगी। वापस जाते समय अचानक उसको चक्कर आया और वह बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ी। उसे आनन-फानन में कुर्सी पर बैठाया गया। होश नहीं आने पर तुरंत सरोजनी नगर CHC ले जाया गया, जहां उसकी हालत स्थिर बताई जा रही है। महिला की पहचान सरोजनी नगर थाने के अनौरा गांव की प्रिया यादव (45) के रूप में हुई है। महिला का जेठ से जमीनी विवाद सरोजनी नगर तहसील न्यायालय में विचाराधीन है। इस जमीन पर न्यायालय के स्टे के बाद भी जेठ निर्माण करा रहे है। इस निर्माण कार्य को रुकवाने के लिए वह समाधान दिवस में शिकायत करने आई थी। महिला प्रिया का पति सत्येंद्र कुमार यादव खेती किसानी करने के साथ ऑटो चलाकर अपने परिवार का भरण-पोषण करता है। सत्येंद्र पिछले काफी दिनों से पाइल्स की बीमारी से पीड़ित है।

महिला को गोद में उठाकर ले जाया गया

लखनऊ के सरोजनी नगर तहसील में शनिवार को समाधान दिवस का आयोजन था। तहसील के अनौरा गांव की प्रिया यादव शिकायत लेकर पहुंची थीं। महिला ने जिलाधिकारी के सामने अपनी बात रखी। इसके बाद वह पीछे हटकर खड़ी हो गईं। अचानक उसे चक्कर आया। वह वहीं बेहोश होकर गिर पड़ी। घटना से मौके पर अफरा-तफरी मच गई। जिलाधिकारी समेत अधिकारी भी हैरान रह गए।

जेठ से चल रहा विवाद

महिला का एक जमीनी विवाद सरोजनी नगर तहसील में न्यायालय में विचाराधीन है। 16 बिस्वा जमीन को लेकर महिला और उसके जेठ इंद्रजीत से विवाद चल रहा है। महिला का आरोप है कि उसके जेठ इन्द्रजीत पूरी जमीन को बेच रहे हैं और उस पर निर्माण कर रहे हैं। महिला को जो हिस्सा दे रहे हैं, वह वन विभाग की जमीन है। वह जब उस पर कुछ करने जाती तो वन विभाग वाले रोक देते हैं। इसको लेकर महिला ने करीब 6 माह पहले सरोजनी नगर एसडीएम न्यायालय में वाद दायर किया था। लेकिन स्टे नहीं मिल रहा है। इसी से परेशान होकर डीएम के सामने शिकायत करने आई थी।

अंतिम निर्णय तक काम रुकवाया जाए

महिला प्रिया ने DM को पत्र देकर बताया कि गाटा संख्या 347, 176, 346 और 813 पर बंटवारे का वाद सरोजनी नगर एसडीएम न्यायालय में विचाराधीन होने के कारण कोई अंतिम निर्णय तक निर्माण कार्य रुकवाया जाए। उसने शिकायत की कि मामला विचाराधीन होने के बावजूद इंद्रजीत यादव और टिंकू यादव अवैध तरीके से तमाम लोगों को लेकर उक्त भूमि पर कब्जा करने का प्रयास कर रहे हैं।

महिला को कुर्सी पर बैठाया गया

घटना के तुरंत बाद, जिलाधिकारी सहित अन्य सभी अधिकारी अपनी कुर्सियों से उठकर महिला के पास पहुंचे। उसे आनन-फानन उठाकर कुर्सी पर बिठाया गया और उसके चेहरे पर पानी छिड़का गया। बाद में, एक सरकारी गाड़ी के माध्यम से महिला को सरोजनी नगर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (सीएचसी) पहुंचाया गया, जहां उसे भर्ती कराया गया है।

5 किलो गैस सिलेंडर के दाम में 261 की बढ़ोत्तरी कर देश को दिया मजदूर दिवस का 'तोहफा' : संजय सिंह

तमसा संकेत, संवाददाता

लखनऊ। आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने मजदूर दिवस के दिन गैस सिलेंडर की कीमतों में भारी बढ़ोतरी को लेकर केंद्र सरकार पर तीखा और सीधा हमला बोला। उन्होंने कहा कि चुनाव खत्म होते ही भाजपा सरकार ने अपनी असलियत दिखाते हुए गरीबों, मजदूरों और छोटे व्यापारियों की जेब पर खुला डाका डाल दिया है। यह कदम साबित करता है कि चुनाव के दौरान किए गए वादे महज छलावा थे और सत्ता हासिल करने का एक सुनियोजित खेल था। संजय सिंह ने कहा कि पूरे चुनाव के दौरान प्रधानमंत्री और भाजपा के नेता गरीबी हटाने, महंगाई कम करने और देश के विकास के नाम पर जनता को गुमराह करते रहे। गरीबों के बीच जाकर दिखावटी संवेदनाएं जताना, उनके साथ भोजन करना, झालमुड़ी खाना और महिलाओं के खातों में पैसे डालने के वादे करना—यह सब एक सुनियोजित राजनीतिक ड्रामा था, जिसका मकसद सिर्फ वोट बटोरना था। उन्होंने कहा कि

चुनाव खत्म होते ही भाजपा का असली चेहरा बेनकाब हो गया। मजदूर दिवस जैसे दिन, जब पूरा देश मजदूरों के सम्मान की बात करता है, उसी दिन 5 किलो के गैस सिलेंडर पर 261 रुपये की बढ़ोतरी कर दी गई। यह सीधा हमला उन झुग्गीवासियों, मजदूरों, गरीबों और छात्रों पर है, जो अपनी रोजमर्रा की जिंदगी चलाने के लिए इस छोटे सिलेंडर पर निर्भर हैं। संजय सिंह ने आगे कहा कि कमर्शियल गैस सिलेंडर, जिसका इस्तेमाल छोटे दुकानदार, ठेले वाले और चाय विक्रेता (जो मोदी जी स्वयं भी खुद को बताते हैं) वो लोग करते हैं, उसकी कीमत में भी 993 रुपये की भारी बढ़ोतरी कर दी गई है। यह फैसला छोटे कारोबारियों की कमर तोड़ने वाला है और इससे बाजार में महंगाई और तेजी से बढ़ेगी। उन्होंने कहा कि भाजपा चुनाव के दौरान जनता को बड़े-बड़े सपने दिखाती है, लेकिन चुनाव खत्म होते ही उन्हीं लोगों के पेट और जेब पर वार करती है। यह सरकार गरीब विरोधी, मजदूर विरोधी और पूरी तरह से जनविरोधी नीतियों पर चल रही है, जो जनता के साथ खुला विश्वासघात है। संजय सिंह ने देश की जनता से आह्वान किया कि वे भाजपा के झूठे वादों और दावों की सच्चाई को समझें और सतर्क रहें। उन्होंने कहा कि जनता को हर वादे की जांच करनी चाहिए और यह देखना चाहिए कि सरकार किस तरह से उनके साथ छल कर रही है, ताकि भविष्य में ऐसे धोखे से बचा जा सके।

फास्ट न्यूज

आईपीएल में 70 लाख हारने पर प्रॉपर्टी-डीलर का सुसाइड

लखनऊ। 'मैं अपना सबकुछ हार गया हूं। मेरी सारी जमा पूंजी चली गई। मेरे पास अब कुछ नहीं बचा है। इसका जिम्मेदार मैं खुद हूं। सॉरी शिवानी...।' ये आखिरी बातें प्रॉपर्टी डीलर प्रबल जैन ने अपनी पत्नी से फोन पर कीं। आखिरी कॉल में दोनों के बीच करीब 25 मिनट तक बात हुई। पत्नी के काफी समझाने के बावजूद प्रबल नहीं माना। इसके बाद लखनऊ में जनेश्वर अपार्टमेंट की 11वीं मंजिल से कूद गया।

अजय राय आईसीयू में, मोदी के बाद राहुल का पोस्ट

लखनऊ। यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष अजय राय की शुक्रवार दोपहर अचानक तबीयत बिगड़ गई। वे बेहोश हो गए। उन्हें तत्काल मेदांता हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। इमरजेंसी में एक्सपर्ट डॉक्टरों की निगरानी में उनका इलाज हुआ। इसके बाद उन्हें ICU में शिफ्ट कर दिया गया। फिलहाल, उनकी हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है। अजय राय को सीने में दर्द की शिकायत हुई थी। घर जाते वक्त कार में ही बेहोश हो गए थे। पीएम मोदी ने शुक्रवार रात 11.54 बजे 'X' परे पोस्ट कर अजय राय के जल्द ठीक होने की कामना की। उन्होंने लिखा- 'यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय के अस्वस्थ होने का समाचार मिला। मैं उनके जल्द से जल्द स्वस्थ होने की कामना करता हूं।' इसके करीब 11 घंटे के बाद शनिवार सुबह 11.13 बजे कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने ट्वीट किया।

कानपुर में ऑयो कमरे में मिला युवक का शव

कानपुर। कानपुर के बिधनू में स्थित एक oyo के कमरे में युवक का शव संदिग्ध परिस्थितियों में पड़ा मिला है। साथियों की सूचना पर पहुंची पुलिस ने फोरेंसिक टीम बुलाकर घटनास्थल से साक्ष्य जुटाने के साथ युवक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। पुलिस जांच में सामने आया कि देर रात सड़क हादसे के बाद तीनों होटल में रुके थे, सिर पर चोट लगने से युवक की मौत हो गई।

भाजपा-बसपा के कई नेताओं ने थामा सपा का दामन

अखिलेश यादव की मौजूदगी में सदस्यता ग्रहण

तमसा संकेत, संवाददाता

लखनऊ स्थित समाजवादी पार्टी के राज्य मुख्यालय में आज एक अहम राजनीतिक घटनाक्रम देखने को मिला। अखिलेश यादव के नेतृत्व में भाजपा और बसपा के कई नेताओं ने समाजवादी पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। सपा में शामिल हुए सभी नेताओं ने एकजुट होकर 2027 विधानसभा चुनाव में पार्टी को जीत दिलाने और अखिलेश यादव को पुनः मुख्यमंत्री बनाने का संकल्प लिया। इस मौके पर दयाराम प्रजापति (पूर्व मंत्री), विजेंद्र प्रजापति, पवन प्रजापति, कालीचरण प्रजापति, सुनील प्रजापति, मानवेन्द्र प्रजापति, राकेश गोला, सुजित प्रजापति, अमित प्रताप सिंह (महानगर अध्यक्ष छात्र सभा), रितिक प्रजापति (महानगर अध्यक्ष लोहिया वाहिनी) और निखिल निगम समेत कई नेता मौजूद रहे।

पुलिस मुख्यालय में तैनात दरोगा ने की आत्महत्या

सुसाइड नोट में लिखा-'जीने की इच्छा खत्म', उम्र 34 साल, शादी से गर्लफ्रेंड ने किया था इनकार

तमसा संकेत, एजेंसी

लखनऊ। लखनऊ में 34 साल के दरोगा ने सुसाइड कर लिया। उनका शव किराए के कमरे में फंदे से लटकता मिला। ASI सत्येंद्र वर्मा, पुलिस मुख्यालय पर तैनात थे। पुलिस को मिले चार पन्नों के सुसाइड नोट में लिखा- अब जीने की इच्छा खत्म हो गई है। शुक्रवार का यह मामला सुशांत गोल्फ सिटी के अहिमामऊ का है। दरोगा मूलरूप से फतेहपुर के तामेश्वर नगर के रहने वाले थे। पुलिस की प्राथमिक जांच में पता चला कि दरोगा की डेढ़ साल पहले इंस्टाग्राम पर युवती से मुलाकात हुई थी। दोनों शादी करना चाहते थे लेकिन बाद में ब्रेकअप हो गया था। वजह थी कि उसके पिता-भाई रिश्ते के खिलाफ थे। इसके बाद से दरोगा तनाव में थे। मां ने गर्लफ्रेंड पर पैसों के लिए परेशान करने का आरोप लगाया। पुलिस परिजन के आरोपों की भी जांच कर रही है। ASI सत्येंद्र वर्मा, 2023 में एएसआई (एम) के पद पर

सतेंद्र वर्मा, मृतक

भर्ती हुए थे। लखनऊ पुलिस मुख्यालय में उनकी तैनाती 25 मार्च, 2024 को पासिंग आउट परेड के बाद की गई थी। लखनऊ के अहिमामऊ में किराए के कमरे में रहते थे। हालांकि, दरोगा की मां सुखरानी देवी ने एक इंस्टाग्राम फ्रेंड पर ब्लैकमेल कर पैसा लेने का आरोप लगाया है। मां के अनुसार, करीब डेढ़ साल पहले सतेंद्र की पहचान इंस्टाग्राम के जरिए एक युवती से हुई थी। दोनों शादी करना चाहते थे, लेकिन युवती के पिता और भाई के विरोध के कारण रिश्ता टूट गया। इसके बाद युवती ने सतेंद्र से पैसों की मांग शुरू कर दी थी और उसके परिजन सतेंद्र को जान से मारने की धमकी भी देते थे।

दो दिन से मां के कॉल का जवाब नहीं दे रहे थे

दरोगा के चचेरे भाई देवेंद्र वर्मा ने बताया- नौकरी के साथ-साथ वह सिविल सर्विसेस परीक्षा की तैयारी कर रहा था। दो दिन से मां कॉल कर रही थी, लेकिन उसने रिसीव नहीं किया। कॉल रिसीव नहीं करने पर परिजन परेशान हुए तो मुझे बताया। शुक्रवार को मैं भाई के कमरे पर पहुंचा, तो कमरा अंदर से बंद था। अनहोनी की आशंका में मैंने पुलिस को सूचना दी। पुलिस पहुंची और दरवाजा तोड़ा गया तो वह फंदे से लटक रहा था।

सुसाइड नोट में लिखा- मेरी आत्महत्या का कोई भी व्यक्ति जिम्मेदार नहीं

पुलिस को एएसआई सत्येंद्र वर्मा के कमरे से एक सुसाइड नोट मिला है। बताया जा रहा कि इस लेटर में आत्महत्या के लिए किसी को दोषी नहीं ठहराया है। पुलिस के अनुसार, सुसाइड नोट में लिखा है कि वह पिछले कुछ दिनों से किसी बात को लेकर तनाव में थे। उन्होंने सबसे माफी भी मांगी है। बताया कि वह 2014 में भी काफी परेशान थे, जिसकी जानकारी परिजन को है। उस समय उन्होंने आत्महत्या के बारे में नहीं सोचा था, लेकिन अब जीने की इच्छा खत्म हो गई है। मां सुखरानी के अनुसार, सतेंद्र के पिता की मौत 2011 में हो चुकी थी। वे राजस्व विभाग में कानूनगो पद से रिटायर हुए थे। तीन बहनें संध्या, मधु और नेहा वर्मा हैं। सत्येंद्र तीसरे नंबर पर थे। वह घर के एकमात्र कमाने वाले सदस्य थे।

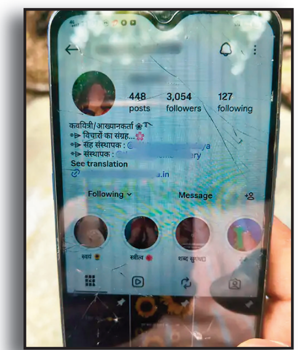

दरोगा को परेशान करने का जिस युवती पर आरोप लगा वह सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव है। वह खुद को कवयित्री बताती है।

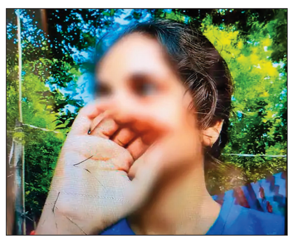

मां ने बताया- दरोगा बेटे का युवती से परिचय इंस्टाग्राम पर हुआ था।

भाजपा पर बरसे अखिलेश यादव, बोले- अर्थव्यवस्था चौपट, जनता त्रस्त

कार्यकर्ताओं से संवाद के दौरान सपा प्रमुख ने 2027 चुनाव की तैयारी तेज करने का दिया आह्वान

तमसा संकेत, संवाददाता

लखनऊ। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने भाजपा सरकार पर तीखा हमला बोला है। शनिवार को पार्टी के प्रदेश मुख्यालय में विभिन्न जिलों से आए कार्यकर्ताओं और नेताओं से मुलाकात के दौरान उन्होंने कहा कि भाजपा ने देश की अर्थव्यवस्था को बर्बाद कर दिया है। महंगाई और बेरोजगारी चरम पर है, जबकि रुपया डॉलर के मुकाबले लगातार कमजोर हो रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रदेश में भ्रष्टाचार और लूट की स्थिति चरम पर पहुंच चुकी है। हर विभाग में बजट की बंदरबांट हो रही है और जनता सरकार की नीतियों से परेशान है। सपा प्रमुख ने दावा किया कि प्रदेश की जनता भाजपा के खिलाफ है और पीडीए (पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक) समाज समाजवादी पार्टी के साथ एकजुट हो रहा है, जिससे

भाजपा घबराई हुई है। अखिलेश यादव ने भाजपा पर झूठा प्रचार करने का आरोप लगाते हुए कहा कि पार्टी का रवैया संविधान और लोकतंत्र के खिलाफ है। उन्होंने कहा कि विधानसभा चुनाव में हार के डर से भाजपा बौखलाई हुई है और अराजकता पर उतर आई है। महिला आरक्षण कानून को लेकर भी उन्होंने भाजपा पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि संसद में पारित हो चुके कानून को लेकर जनता को गुमराह किया जा रहा है। साथ ही संवैधानिक पदों पर बैठे लोग भी भ्रम फैलाने का काम कर रहे हैं। सपा प्रमुख ने प्रीपेड और स्मार्ट मीटर को लेकर भी सरकार को घेरा। उन्होंने कहा कि टेक्नोलॉजी के नाम पर जनता की जेब से पैसे वसूले जा रहे हैं और बिजली विभाग में भ्रष्टाचार बढ़ा है। उन्होंने दावा किया कि अब जनता भाजपा की "चोरी" को समझ चुकी है और उसके खिलाफ आक्रोश सड़कों पर दिखाई दे रहा है। उन्होंने भाजपा पर संविधान और लोकतंत्र विरोधी रवैया अपनाने का आरोप लगाया। साथ ही कहा कि महिला आरक्षण कानून को लेकर भ्रम फैलाया जा रहा है। अखिलेश यादव ने स्मार्ट और प्रीपेड मीटर को लेकर भी सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि तकनीक का दुरुपयोग कर जनता से वसूली की जा रही है। साथ ही ईवीएम को लेकर भी सवाल उठाए। उन्होंने भाजपा पर संविधान और लोकतंत्र विरोधी रवैया अपनाने का आरोप लगाया।

हादसा : कानपुर में खराब खड़े मौरंग लदे डंपर से टक्कर, 3 घंटे तक मदद के लिए चिल्लाते रहे

डंपर से टकराकर केबिन में फंसे 2 भाई...तड़पकर मौत

तमसा संकेत, एजेंसी

कानपुर। कानपुर में मौरंग लदे खराब खड़े डंपर में पीछे से आ रहा डंपर जा घुसा। टक्कर इतनी जोरदार थी की पीछे से टकराने वाले डंपर का केबिन चिपक गया। उसके केबिन में बैठे ड्राइवर और उसके हेल्पर की मौत हो गई। दोनों सगे भाई थे। दोनों करीब 3 घंटे तक केबिन में फंसे रहे। सूचना पर पुलिस पहुंची। दोनों को निकालने की कोशिश की गई। लेकिन कामयाबी नहीं मिली। क्रेन मंगाना पड़ा। करीब तीन घंटे तक जिंदगी के लिए लड़ते हुए दोनों भाइयों ने दम तोड़ दिया। बाद में दो क्रेन की मदद से मौरंग लदे दोनों डंपर को आगे पीछे खींचने के बाद उनके शवों को बाहर निकाला जा सका। हादसा शनिवार की सुबह नौबस्ता एलिवेटेड पुल पर हुआ। इस हादसे के बाद हाईवे पर करीब दो किमी तक वाहनों की लंबी कतार लग गई।

दो क्रेनों ने दोनों भाइयों को निकाला गया

बुरी तरह से केबिन में फंसे दोनों भाई मदद के लिए गुहार लगाते रहे। करीब एक घंटे की मशक्कत के बाद भी दोनों भाईयों ने नहीं निकाला जा सका।

इसके बाद पुलिस ने मौके पर दो क्रेनें मंगवाई और फिर दोनों मौरंग लदे डंपर को आगे पीछे करके हटाया गया।

इसके बाद केबिन खींचकर दोनों को भाइयों को बाहर निकाला गया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी।

अमन ने बताया कि सुबह 4:30 बजे दीपक से बात हुई थी। उसने बताया था कि वह नौबस्ता पहुंचने वाले हैं। उसके आधे घंटे बाद उससे हादसे की जानकारी हुई।

पृष्ठ 01 का शेष...

15 बूथों पर...

इसके अलावा सभी विधानसभा क्षेत्रों में महिलाएं स्ट्रांग रूम पर धरना देंगी। कोलकाता पुलिस ने कालीघाट पुलिस स्टेशन के ऑफिसर इन चार्ज गौतम दास को सस्पेंड कर दिया है। उन्होंने सोशल मीडिया पर एक बंदूक के साथ एक तस्वीर पोस्ट की थी, जिस पर लिखा था 'नए काम के लिए तैयार'। कालीघाट PS की नई ऑफिसर इन-चार्ज चमेली मुखर्जी हैं। पश्चिम बंगाल के श्यामपुकुर से TMC उम्मीदवार शशि पांजा ने कहा- EVM के कुछ बटन पर टेप लगा हुआ था, इसी वजह से दोबारा वोटिंग हो रही है, और यह बात समझ में आती है। EC को यह देखना चाहिए कि बटन पर टेप किसने लगाया था। लोगों को अब यह एहसास हो गया है कि जैसे ही वोटिंग का दूसरा चरण खत्म हुआ, LPG की कीमतें बढ़ गईं। TMC ने हमेशा कहा था कि चुनाव खत्म होते ही LPG की कीमतें बढ़ जाएंगी। लोगों ने यह देख लिया है और अब आप कितनी भी बार दोबारा वोटिंग करवा लें, TMC ही जीतेगी। डायमंड हार्बर के फालता में स्थानीय लोगों ने आरोप लगाया है कि इलाके में दूसरे फेज में वोटिंग हुई थी। इसके बाद टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने हमारे घरों में घुसकर मारपीट की। हम आज इस घटना का विरोध कर रहे थे तो बंगाल पुलिस ने हम पर लाठीचार्ज किया है। फलता वही इलाका है, जहां बीजेपी ने आरोप लगाया था कि यहां पर ईवीएम में बीजेपी के बटन पर टेप लगाया गया था। दक्षिण 24 परगना में री-पोलिंग के दौरान भाजपा और टीएमसी समर्थकों के बीच झड़प का दावा। कोलकाता के श्यामपुकुर से टीएमसी उम्मीदवार शशि पांजा ने कहा है कि ईवीएम के कुछ बटनों पर टेप लगा दिया गया था, जिसके कारण पुनर्मत-दान कराना पड़ रहा है। यह जांचना चाहिए कि वे बटन किसने टेप किए थे।

अमेरिका की हर...

उनका मकसद पहले तेल की कीमतों को गिरने से रोकना और दूसरा अपनी बनाई हुई मुश्किल स्थिति से बाहर निकलना है। वहीं, अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्प ने कहा कि वे ईरान को किसी भी हालत में परमाणु हथियार हासिल नहीं करने देंगे, क्योंकि यह पूरी दुनिया की सुरक्षा के लिए एक बड़ा खतरा है। इसी वजह से अमेरिका को ईरान के खिलाफ जंग में उतरना पड़ा। अधिकारी ने नाम न बताने की शर्त पर कहा कि ईरान का मानना है कि परमाणु मुद्दे को बाद में रखने से समझौता करना आसान हो सकता है। यह प्रस्ताव डोनाल्ड ट्रम्प ने फिलहाल खारिज कर दिया है। इस प्रस्ताव के तहत अगर समझौता होता है, तो युद्ध खत्म हो जाएगा और इजराइल और अमेरिका दोबारा हमला नहीं करने का वादा करेंगे। इसके बदले में ईरान समुद्री रास्ता खोल देगा और अमेरिका अपनी पाबंदियां हटा लेगा। UAE में एयर ट्रैफिक नॉर्मल हो रहा है। UAE सिविल एविएशन अथॉरिटी ने बताया कि पहले सुरक्षा कारणों से कुछ समय के लिए नियम सख्त किए गए थे, लेकिन अब उन्हें हटा दिया गया है। अधिकारियों ने कहा कि अब हालात ठीक हैं, इसलिए फ्लाइट्स पहले की तरह चल रही हैं। हालांकि अभी भी सुरक्षा के मुद्देनजर हालात पर नजर रखी जा रही है। यमन के कोस्टगार्ड ने बताया है कि कुछ हथियारबंद लोगों ने M/T Eureka नाम के तेल टैंकर को हाईजैक कर लिया है। यह घटना शबवा प्रांत के तट के पास हुई। हमलावर जहाज पर चढ़ गए, उस पर कब्जा कर लिया और उसे अदन की खाड़ी की ओर यानी सोमालिया के समुद्री इलाके में ले गए। इससे पहले यूके मैरीटाइम ट्रेड ऑपरेशंस ने भी जानकारी दी थी कि अल-मुकल्ला बंदरगाह से करीब 84 समुद्री मील दूर एक जहाज के पास संदिग्ध तरीके से एक हरे रंग की छोटी नाव (स्किफ) और एक मछली पकड़ने वाली नाव देखी गई थी। चीन के संयुक्त राष्ट्र में राजदूत फू कॉन्ग ने कहा है कि ईरान-अमेरिका में युद्धविराम बनाए रखना और होर्मुज स्ट्रेट को फिर से खोलना अभी सबसे जरूरी मुद्दे हैं। उन्होंने कहा कि अगर होर्मुज बंद रहता है, तो यह मुद्दा शी जिनपिंग और डोनाल्ड ट्रम्प के बीच होने वाली बातचीत में प्रमुख रहेगा। फू कॉन्ग के मुताबिक, यह मामला दोनों देशों की मीटिंग के एजेंडा में सबसे ऊपर हो सकता है। यूके मैरीटाइम ट्रेड ऑपरेशंस (UKMTO) ने बताया कि यमन के पास समुद्र में कुछ संदिग्ध हरकत देखी गई है। यह घटना अल-मुकल्ला शहर से करीब 84 समुद्री मील दूर हुई, जहां एक जहाज के पास कोई संदिग्ध चीज या नाव आई। UKMTO ने सभी जहाजों से कहा है कि इस इलाके में जाते समय सावधान रहें और अगर कुछ भी अजीब दिखे तो तुरंत खबर दें। ईरान में लोग ठीक से इंटरनेट इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं। इससे काम-धंधा, नौकरी और रोज की जिंदगी पर बुरा असर पड़ रहा है। इंटरनेट पर नजर रखने वाली संस्था नेटब्लॉक्स के मुताबिक, ईरान में 64 दिनों से यह हालत बनी हुई है। ईरान ने अमेरिकी जनता से कहा है कि वे अपनी सरकार से सवाल करें। ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बघाई ने कहा कि अमेरिका और इजराइल ने जबरदस्ती और गैर कानूनी युद्ध शुरू किया। उन्होंने कहा कि अमेरिकी जनता का यह अधिकार और जिम्मेदारी है कि वे ट्रम्प की सरकार से जवाब मांगे कि यह युद्ध क्यों किया गया। इस्माइल बघाई ने आरोप लगाया कि ईरान पर हमला बिना किसी उकसावे के किया गया और इसमें कई गलत काम हुए हैं। उन्होंने एक वीडियो भी शेयर किया, जिसमें अमेरिकी सांसद किर्स्टन गिलिब्रैंड सीनेट (संसद) की सुनवाई में कह रही हैं कि हमारे पास ऐसा कोई सबूत नहीं था।

अंकित हत्याकांड में 3 आरोपी गिरफ्ता

दोस्त ने कार बुक कर की हत्या, शव गंगा में फेंका

तमसा संकेत, एजेंसी

कानपुर। डीसीपी पूर्वी ने शनिवार को 17 अप्रैल से लापता अंकित की हत्या का खुलासा किया। पुलिस ने इस मामले में तीन आरोपियों रेहान, शादाब और अल्तमश को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। पुलिस के अनुसार, अंकित के दोस्त सत्यम ने योजना बनाकर मृतक की कार बुक करवाई और उसे फतेहपुर ले गया। मुख्य आरोपी सत्यम बाइक से पीछे चल रहा था। आरोपियों ने अंकित का गला तब दबाया जब उसने कार का पासवर्ड बताने से इनकार कर दिया। हत्या के बाद शव को फतेहपुर के सुल्तान घोष स्थित गंगा नदी में फेंक दिया गया। पुलिस अभी तक शव बरामद नहीं कर पाई है। शव की तलाश में फतेहपुर पुलिस, कानपुर पुलिस और एनडीआर-एफ की टीमें जुटी हुई हैं।

तमसा संकेत
tamsa.newslko@gmail.com

स्वत्वाधिकारी, मुद्रक, प्रकाशक विद्या देवी द्वारा कृष्णा डाइनेस्टी प्रिंटिंग प्रेस म0 न0 195 सेक्टर 6-बी, वृन्दावन योजना, रायबरेली रोड लखनऊ-226 029 (उ0प्र0) से मुद्रित व प्रकाशित।

सम्पादक : विद्यादेवी

समस्त विवादों का न्याय क्षेत्र लखनऊ होगा

समाचार पत्र में प्रकाशित लेख, राजनीतिक विश्लेषण, लेखकों के अपने विचार हैं। सम्पादक का इन विचारों से सहमत होना आवश्यक नहीं हैं।
मो0- 9415799533
R.N.I. NO. UPHIN/2021/83676